



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-आ.-07012021-224277
CG-DL-E-07012021-224277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]
No. 7]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 7, 2021/पौष 17, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 7, 2021/PAUSAH 17, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2021

मामला सं. एडीडी-ओआई - 32/2019

विषय: चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 6/36/2019-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" भी कहा गया है) तथा उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा धनि के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए:

क. मामले की पृष्ठभूमि

- निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकार्ता" भी कहा गया है) से चीन जनतांत्रिक गणतंत्र (जिसे आगे "संबद्ध देश" भी कहा गया है) से "सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड" अथवा "सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल" (जिसे आगे "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" अथवा "संबद्ध सामान" भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क (पाटित आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे आगे “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार टीपीएम कन्सलटेंट के माध्यम से आवेदन प्राप्त हुआ। मैसर्स गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड, संबद्ध वस्तुओं का एक अन्य घरेलू उत्पादक ने आवेदक द्वारा दायर आवेदन-पत्र का समर्थन किया।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध सामानों के तथाकथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव निर्धारित करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि, जो यदि लगायी जाए और घरेलू उद्योग को तथाकथित क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए नियमावली के नियम 5 के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 10 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 6/36/2019-डीजीटीआर द्वारा एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
3. इस अधिनियम और नियमावली पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने इसे उपर्युक्त माना कि अंतरिम शुल्क की सिफारिश की जाए और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हुए दिनांक 15 जून, 2020 की अधिसूचना सं.6/36/2019-डीजीटीआर के संदर्भ में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया। तदनुसार, दिनांक 2 सितंबर, 2020 की अधिसूचना सं. 28/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के संदर्भ में केन्द्र सरकार ने चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया जो छह महीने के लिए वैध है।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया अपनाई गई है:
 - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली 5 के उपनियम (5) के अनुसार जांच की शुरूआत करने से पूर्व वर्तमान पाटनरोधी जांच संबंधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित दिनांक 10 जनवरी, 2020 की सार्वजनिक सूचना जारी की।
 - ग. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार, जांचों की शुरूआत करने के संबंध में सूचित किया गया था। प्राधिकारी ने संबद्ध देश की सरकार को भारत में उसके दूतावास के माध्यम से, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग और आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार अन्य घरेलू उत्पादकों को जांच की शुरूआत की अधिसूचना की प्रति भेजी और उनसे अनुरोध किया कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित में अपने ज्ञात विचार दें। प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना मंगाने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजीं:
 - i. मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि.
 - ii. मैसर्स झेजियांग जिंकिसन फार्मास्युटिकल इम्पॉ.
 - iii. मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि.

- च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे चीन जन.गण. के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ उन्हें भेजी गई थी।
- छ. संबद्ध जांच की शुरूआत के उत्तर में संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दायर किया:
- i. मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं.लि .
 - ii. मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं.लि .
 - iii. मैसर्स झेजियांग जिंकिसन फार्मास्युटिकल इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं.लि .
 - iv. मैसर्स शंघ्यु जिंकिसन फार्मास्युटिकल्स कं.लि .
- ज. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाते हुए भारत में संबद्ध सामानों के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी:
- i. मैसर्स फार्मा जोन
 - ii. मैसर्स शालीना लैबोरेट्रीज प्रा.लि .
 - iii. मैसर्स मिनर्वा बायोजेनिक्स प्रा.लि .
 - iv. मैसर्स पिनेकल लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड
 - v. मैसर्स लैबोरेट फार्मास्युटिकल इंडिया लिमिटेड
 - vi. मैसर्स स्नेहा मेडिकेयर प्रा.लि .
 - vii. मैसर्स एफ्रिक्योर फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड प्राइवेट (इंडिया)
 - viii. मैसर्स डेल ट्रेड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
 - ix. मैसर्स सेवांतिलाल एंड संस
 - x. मैसर्स बाल फार्मा लिमिटेड
 - xi. मैसर्स प्रतिष्ठा फार्मा
 - xii. मैसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड
 - xiii. मैसर्स सी जे शाह एंड कं.
 - xiv. मैसर्स मेडिको रेमेडीज लिमिटेड
 - xv. मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - xvi. मैसर्स कड़ीला फार्मास्युटिकल्स लि.
 - xvii. मैसर्स फ्लेमिंगो फार्मास्युटिकल्स लि.
 - xviii. मैसर्स प्राशी फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 - xix. मैसर्स सिनकोम फॉर्मूलेशन्स (इंडिया) लिमिटेड
 - xx. मैसर्स माइक्रो लैब्स लि.
 - xxi. मैसर्स मेनकेयर फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
 - xxii. मैसर्स गोरांग इंटरनेशनल
 - xxiii. मैसर्स ग्रेन्यूल्स इंडिया लिमिटेड

- xxiv. मैसर्स ब्रॉन लैबोरेट्रीज लि.
- xxv. मैसर्स थियोन फार्मास्युटिकल्स लि.
- xxvi. मैसर्स अगोग फार्मा लि.
- xxvii. मैसर्स एक्स्ट्राटिक रेमेडीज लिमिटेड
- xxviii. मैसर्स मेडोफार्म
- xxix. मैसर्स उमेडिका लैबोरेट्रीज प्रा. लि.
- झ. मैसर्स माइक्रो लैब लिमिटेड को छोड़कर किसी भी आयातक/प्रयोक्ता ने उत्तर नहीं दिया है और आयातक प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया।
- ज. प्राधिकारी ने निम्नलिखित अन्य घरेलू उत्पादकों को निर्धारित स्वरूप एवं तरीके में प्राधिकारी को संगत सूचना उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ जांच की शुरूआत के संबंध में उन्हें सूचित करते हुए जांच की शुरूआत की सूचना भेजी:
- i. मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - ii. मैसर्स डॉ. रेहुं लैबोरेट्रीज लि.
 - iii. मैसर्स न्यूलैंड लैबोरेट्रीज लिमिटेड
 - iv. मैसर्स एम्मेनार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 - v. मैसर्स श्रीपति फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 - vi. मैसर्स सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.
- ट. किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया अथवा वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया।
- ठ. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए खुले में रखी गई सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों/किए गए अनुरोधों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस स्तर पर संगत समझी गई सीमा तक किए गए अनुरोधों को इन अंतिम जांच परिणामों में ध्यान में रखा गया है।
- ड. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछले तीन वर्षों तथा जांच की अवधि के लिए संबद्ध सामानों के आयातों के लेन-देन वार ब्यौरे उपलब्ध कराएं जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गए थे। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा एवं मूल्य का परिकलन करने और लेन-देनों की उचित जांच करने के बाद अपने विश्लेषण के लिए डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया है।
- ढ. सामान्यतया स्वीकृति लेखाकरण सिद्धांतों (जीएएपी) और नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध सामानों की उत्पादन लागत और निर्माण एवं बिक्री लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- ण. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रादुर्भाव और भारत सहित विभिन्न देशों द्वारा लगाए गए परिणामी प्रतिबंधों के कारण, इस सूचना का मौके पर सत्यापन के माध्यम से प्राधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण नहीं किया गया था। आवेदक/उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन उस सीमा तक प्राधिकारी द्वारा किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना गया। जिस सीमा तक इसे आवश्यक माना गया उस सीमा तक आवश्यक सुधार के साथ केवल ऐसी सत्यापित सूचना पर इन अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्य से विचार किया गया है।

- त. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अन्य अनुरोधों पर इन अंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त रूप से विचार किया गया है जिस सीमा तक इसके समर्थन में साक्ष्य था और जिस सीमा तक इसे वर्तमान जांच के लिए संगत माना गया।
- थ. वर्तमान पाटनरोधी जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि अप्रैल, 2018 – जून, 2019 (15 माह) है। क्षति विशेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल, 2015 – मार्च, 2016, अप्रैल, 2016 – मार्च, 2017, अप्रैल, 2017 – मार्च, 2018 की अवधियां तथा जांच की अवधि शामिल हैं।
- द. कोविड-19 के विश्वव्यापी प्रादुर्भाव और भारत सहित अलग-अलग देशों द्वारा लगाए गए परिणामी प्रतिबंधों के कारण, प्राधिकारी ने दिनांक 10 अप्रैल, 2020 की व्यापार सूचना संख्या 01/2020 तथा पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार इन हितबद्ध पक्षकारों को तत्कालीन पदस्थ निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष मौखिक रूप से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अवसर देने के वास्ते दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 को वीडियो कानफ्रेंसिंग के माध्यम से मौखिक सुनवाई की।
- ध. सभी पक्षकारों जिन्होंने उपर्युक्त मौखिक सुनवाई में भाग लिया था को सलाह दी गई थी कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित अनुरोध और उसके बाद प्रति उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें। इन हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त ऐसे लिखित अनुरोधों और प्रति उत्तरों में दिए गए तर्कों पर इन अंतिम जांच परिणामों के उद्देश्यों से उस सीमा तक विचार किया गया है जिस सीमा तक उन्हें आवश्यक माना गया।
- न. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध जिनमें प्रारंभिक जांच परिणाम के उत्तर में किया गया अनुरोध शामिल है, पर प्राधिकारी द्वारा जहां कहीं भी संगत पाया गया इन अंतिम जांच परिणामों में चर्चा की गई है।
- प. गोपनीय आधार पर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्यासिता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्यास अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- फ. प्राधिकारी ने इस स्तर तक सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए तर्कों और दी गई सूचना पर उस सीमा तक विचार किया है जहां तक वे साक्ष्य से युक्त हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत माने गए हैं।
- ब. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से इंकार किया है अथवा वर्तमान जांच क्रिया के दौरान अन्यथा आवश्यक सूचना नहीं दी है अथवा जांच में काफी बाधा ढाली है उन ने प्राधिकारी वहां, किए रिकार्ड परिणाम जांच प्राथमिक पर आधार के तथ्यों उपलब्ध तथा है माना असहयोगी को पक्षकारों हैं।
- भ. इन अंतिम जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकारा द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई तथा प्राधिकारी द्वारा नियमावली के तहत मानी गई सूचना दर्शाते हैं।
- म. प्राधिकारी द्वारा की जांच की अवधि के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर= 70.73 रुपए है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच की शुरुआत के स्तर पर विचाराधीन उत्पाद निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया था:

"विचाराधीन उत्पाद "सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोरोइड" अथवा "सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल" है।

सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोरोइड का उपयोग चर्म संक्रमण, हड्डी तथा जोड़ के संक्रमण, सांस अथवा साइनस संक्रमण, मूत्र नलिका संक्रमण और कृतिपय प्रकार के डायरिया सहित विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। यह एंटीइंफैक्टिव एजेंट, टोपाइसोमिरास /V इनहिबिटर, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एक ईसी 5.99.1.3 [डीएनए टोपाइसोमिरास (एटीपी-हाइड्रोलाइजिंग)] इनहिबिटर, एक डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, एक एंटी माइक्रोबायल एजेंट, एक इनवायरमेंटल कंटेनर्स में तथा एक जिनोबायटिक के रूप में कार्य करता है।

विचाराधीन उत्पाद "सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल अथवा उसके साल्ट" (उप शीर्ष 29419030) के नाम में सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क) विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल है, जो क्लीनोलिन है अर्थात् क्लीनोलिन-4 (एच)-साइक्लोप्रोपिल से युक्त, कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्लोरो और पीपराजिन-1-वार्झएल प्रतिस्थापक है जो क्रमशः 1, 3, 6 और 7 स्थिति पर है।
- ख) विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की निर्धारित यूनिट कि.ग्रा./मी. टन में भार है।
- ग) सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल अथवा उसके साल्ट के नाम में सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सिप्रोफ्लोक्सासिन और उसके साल्ट के लिए समर्थित कोड 29419030 है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- घ) आवेदक द्वारा उत्पादित सामान आयातित सामानों की समान वस्तु हैं क्योंकि वे रासायनिक एवं तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियों, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा सामानों के प्रशुल्क वर्गीकरण के संबंध में तुलनीय हैं और तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
- ड) घरेलू उद्योग द्वारा और संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा लगाई गई प्रौद्योगिकी में कोई विशेष ज्ञात अंतर नहीं है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- 8. जांच की शुरूआत की सूचना में परिभाषित किए गए अनुसार, विचाराधीन उत्पाद "सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड" अथवा "सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल" है। सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग चर्म संक्रमण, हड्डी तथा जोड़ के संक्रमण, सांस अथवा साइनस संक्रमण, मूत्र नलिका संक्रमण और कतिपय प्रकार के डायरिया सहित विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमणों के उपचार के लिए किया जाता है। यह एंटीइंफॉक्टिव एजेंट, टोपाइसोमिरास IV इनहिबिटर, एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग, एक ईसी 5.99.1.3 [डीएनए टोपाइसोमिरास (एटीपी-हाइड्रोलाइजिंग)] इनहिबिटर, एक डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर, एक एंटी माइक्रोबायल एजेंट, एक इनवायरमेंटल कंटेनर्मेंट तथा एक जिनोबायटिक के रूप में कार्य करता है।
- 9. विचाराधीन उत्पाद सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल अथवा उसके साल्ट के नाम में प्रशुल्क कोड 29419030 के साथ सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 29 के तहत वर्गीकृत है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और वर्तमान जांच के क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।
- 10. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने जांच की शुरूआत के बाद विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में संशोधन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया है। तदनुसार, प्राधिकारी ने इन अनंतिम जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए जांच की शुरूआत की सूचना में परिभाषित किए गए अनुसार विचाराधीन उत्पाद माना है।
- 11. आवेदक ने दावा किया कि उसके द्वारा उत्पादित सिप्रोफ्लोक्सासिन एचसीएल और संबद्ध देश से आयातित उत्पाद समान मूल कड़ी सामग्री का प्रयोग करके उत्पादित किए जाते हैं जिनमें व्यापक रूप से समान विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, प्रकार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विशिष्टियां, वितरण एवं विपणन तथा प्रशुल्क वर्गीकरण हैं। आवेदक के तर्क पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने विवाद नहीं किया है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान नियमावली के नियम 2(घ) के अनुसार संबद्ध देश से आयातित उत्पाद की समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का क्षेत्र एवं आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

12. घरेलू उद्योग के क्षेत्र एवं आधार के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध निम्नलिखित हैं:

- क. यह आवेदन पत्र मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और इसका समर्थन विचाराधीन उत्पाद के दूसरे उत्पादक मैसर्स गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।
- ख. विचाराधीन उत्पाद के द्वारा और ज्ञात घरेलू उत्पादक हैं अर्थातः ,
 - i. मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
 - ii. मैसर्स डॉ. रेड्डी लैबोरेट्रीज लि.
 - iii. मैसर्स न्यूलैंड लैबोरेट्रीज लिमिटेड
 - iv. मैसर्स एम्मेशार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
 - v. मैसर्स श्रीपति फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
 - vi. मैसर्स सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.
- ग. आवेदक न तो भारत में किसी आयातक से संबद्ध है और न ही संबद्ध देश के किसी निर्यातक से तथा उसने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है।
- घ. आवेदक का भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात है और इस प्रकार घरेलू उद्योग है।
- ड. आवेदक ने बाजार सूचना के आधार पर अन्य उत्पादकों के उत्पादन का आकलन किया है क्योंकि कोई प्रकाशित सूचना उपलब्ध नहीं है। प्राधिकारी ने क्षति निर्धारण के संबंध में निर्धारित रूप में और तरीके से सूचना प्रस्तुत करने के लिए उन्हें सलाह देते हुए अन्य घरेलू उत्पादकों को पत्र भेजा। हालांकि अन्य घरेलू उत्पादकों में से किसी भी उत्पादक ने क्षति संबंधी पूर्ण सूचना प्रस्तुत नहीं की है। रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए और प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया साक्ष्य यह दर्शाता है कि आवेदक का बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा है और इस समर्थक के साथ आवेदक का भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक है। किसी भी अन्य उत्पादक ने उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं किया है।
- च. आवेदक घरेलू उद्योग के कुल भारतीय उत्पादन और आधार का आकलन करने के लिए अन्य घरेलू उत्पादकों से सूचना मंगाने के विरुद्ध कभी नहीं था। हालांकि यदि अन्य घरेलू उत्पादकों ने प्राधिकारी को सहयोग नहीं किया है तब घरेलू उद्योग को उसके लिए दंडित नहीं किया जा सकता है।
- छ. प्राधिकारी ने आवेदक की सूचना के आधार पर प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज किया है और चूंकि घरेलू उद्योग को क्षति समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादक के आंकड़ों के आधार पर नहीं तब यह संभावना कि ऐसे घरेलू उत्पादक प्रपत्र के अनुसार सूचना नहीं दी गई होगी, इस निर्धारण को गलत नहीं ठहराता है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

13. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. अन्य सभी उत्पादकों के उत्पादन के वास्तविक प्रतिशत का समर्थन करने के लिए कोई प्रमाण अथवा कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है कि न्यूलैंड्स लैबोरेटरी लिमिटेड और मै. डा. रेड्डीज लैबोरेटरीज लि. ने केवल निर्यात करने के लिए उत्पादन किया है। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, ये दो उत्पादक घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक की बिक्री करते हैं।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

14. नियमावली के नियम 2(ख) में घरेलू उद्योग निम्नलिखित रूप में परिभाषित है:

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से हैं जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाठित वस्तु के

निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

15. यह आवेदन पत्र मैसर्स आरती ड्रग्स लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध सामानों के किसी आयातक अथवा निर्यातक से संबद्ध नहीं है और न ही उन्होंने संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का आयात किया है। आवेदक देश में संबद्ध सामानों का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त, आवेदक द्वारा दायर आवेदन पत्र का समर्थन संबद्ध सामानों के अन्य घरेलू उत्पादक मैसर्स गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड ने किया है। आवेदक और समर्थक के अलावा, भारत में संबद्ध सामानों के अन्य भारतीय उत्पादक निम्नलिखित हैं:

- क. मैसर्स अरबिंदो फार्मा लिमिटेड
- ख. मैसर्स डॉ.लि लैबोरेट्रीज रेडी .
- ग. मैसर्स न्यूलैंड लैबोरेट्रीज लिमिटेड
- घ. मैसर्स एमेन्नार फार्मा प्राइवेट लिमिटेड
- ङ. मैसर्स श्रीपति फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
- च. मैसर्स सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लि.

16. जांच की शुरूआत के स्तर पर और उसके बाद प्राधिकारी ने अन्य घरेलू उत्पादकों को यह सलाह देते हुए एक पत्र भेजा कि वे क्षति निर्धारण के संबंध में निर्धारित प्रपत्र एवं तरीके में सूचना दायर करें। तथापि, किसी भी अन्य घरेलू उत्पादक ने निर्धारित प्रपत्र में क्षति संबंधी पूर्ण सूचना दायर नहीं की है।

17. इस अनुरोध के संबंध में कि याचिका न देने वाले अन्य उत्पादकों के वास्तविक उत्पादन का समर्थन करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के विपरीत साक्ष्य नहीं दिया है। कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने न्यूलैंडस लैबोरेटरी लिमिटेड और मै. डा. रेडीज लैबोरेट्रीज लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट पर विश्वास किया है और यह तर्क दिया कि ये कंपनियां घरेलू बाजार में अपने उत्पादन का 30 प्रतिशत से अधिक बिक्री करते हैं। हालांकि यह नोट किया जाता है कि इन कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट कंपनी के कारोबार का क्षेत्र-वार विश्लेषण दर्शाता है और यह विचाराधीन उत्पादन के लिए विशेष नहीं है।

18. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाता है कि आवेदक का भारत में कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख अनुपात (43 प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त, आवेदक का समर्थक सहित भारत में संबद्ध सामानों के कुल घरेलू उत्पादन में 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है। तदनुसार, प्राधिकारी मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अभिप्राय से घरेलू उद्योग है और मानते हैं कि आवेदन पत्र नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

अ. गोपनीयता

घरेलू उद्योग के विचार

19. गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. आवेदक ने नियमावली के नियम 7 के अनुसार तथा 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना संख्या 10/2018 के अनुसार आवेदन पत्र के अगोपनीय रूपांतर में सभी अनिवार्य सूचनाएं प्रकट की हैं।
- ख. जहां भी संभव हुआ है, सूचीबद्ध सूचना दी गई है। क्षति विश्लेषण अनिवार्य रूप से एक प्रवृत्ति का विश्लेषण है जिसे आवेदन पत्र में दिए गए विभिन्न मानदंडों की प्रवृत्तियों के माध्यम से आसानी से देखा जा सकता है।
- ग. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर उत्तर का अगोपनीय रूपांतर पूर्णतः कमी वाला है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

- घ. झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि. ने शेयरधारण संरचना, उत्पादन प्रक्रिया, पूर्ण मूल्य श्रृंखला तथा उत्पादन सुविधाओं के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। वह अपने संबद्ध पक्षकारों और कद्दी सामग्री की खरीद के ब्यौरे प्रकट करने में विफल रहा है।
- ड. झेजियांग लंघुआ ने उत्पाद सूची और कारपोरेट संरचना को गोपनीय होने का दावा किया है। यद्यपि, वह सार्वजनिक पटल पर उपलब्ध है।
- च. शेंग्यु जिंकिसन फार्मास्युटिकल कं. लि. ने स्वयं कंपनी, धारक कंपनी की कार्यप्रणाली तथा उसके क्रियाकलाप और संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी अन्य संबद्ध कंपनियों की कार्यप्रणाली के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है। इसके अतिरिक्त, उसने अपनी शेयरधारण संरचना, वितरण चैनल, उत्पाद सूची, कद्दी सामग्री खरीद, उत्पाद विवरण और उत्पादन प्रक्रिया के ब्यौरे उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- छ. झेजियांग जिंकिसन फार्मास्युटिकल एक्सपॉर्ट एंड इम्पॉर्ट कं. लि. (व्यापारी) ने अपनी शेयरधारिता संरचना, बिक्री प्रवाह तालिका, संबद्ध सामानों के उत्पादन में लगी अपनी संबद्ध कंपनी (कंपनियों) के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है।
- ज. समर्थन करने वाले उत्पादकों ने आवेदक को न तो संगत सूचना उपलब्ध कराई है और न ही आवेदक के पास यह अधिकार है कि वे उन्हें विवश करें क्योंकि उन्होंने आवेदक को सूचीबद्ध आंकड़ों को भी प्रकट करने के लिए अधिकार नहीं दिया है। सूचीबद्ध आंकड़ों में भी बहुत अधिक सूचना है।
- झ. एनआईपी एक अत्यधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है और उसे वास्तविक आधार पर अथवा एक दायरे में भी प्रकट नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी भी एनआईपी अथवा सामान्य मूल्य या निर्यात कीमत को दायरे में भी प्रकट नहीं करते हैं। हितबद्ध पक्षकार यह मान रहे हैं कि प्राधिकारी बिना किसी जानकारी के कार्रवाई करते हैं।
- ञ. आवेदक ने दिनांक 7 फरवरी, 2020 के पत्र के संदर्भ में पहले ही डीजीसीआईएंडएस लेन-देनवार आयात आंकड़ों का अगोपनीय पाठ प्रस्तुत किया है।
- ट. एनसीवी आवेदन में यह उल्लेख है कि आवेदक के तुलन-पत्र को कंपनियों की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। आवेदक की गुणवत्ता नीति, बिक्री नीति बहुत अधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है जिसके प्रकटन से प्रतिस्पर्धियों को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी लाभ मिलेगा।

अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

20. गोपनीयता के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. व्यापार सूचना संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर, 2018 में "क्षति रहित कीमत" के प्रकटन के लिए दिया गया मानक "कुल वास्तविक आंकड़े वास्तविक आंकड़ों की रेंज +/- 10 प्रतिशत में दिए जाने चाहिए" है। इसका घरेलू उद्योग द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है और घरेलू उद्योग ने इस प्रकोर की गोपनीयता के लिए कोई सही कारण भी नहीं दर्शाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एनआईपी जानबूझकर छिपाया गया होगा क्योंकि संबद्ध आयातों की आयात कीमत क्षति-रहित कीमत की तुलना में अधिक है।
- ख. गोदावरी ड्रग्स लिमिटेड संबद्ध जांच में एक समर्थक घरेलू उत्पादक है। व्यापार सूचना संख्या 13/2018 दिनांक 27 सितंबर, 2018 में उल्लेख है कि समर्थक घरेलू उत्पादकों द्वारा सूचना तथा उसके लिए निर्धारित प्रपत्र दिया जाना अपेक्षित है। व्यापार सूचना 14/2018 दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 यह सूचना गोपनीय एवं अगोपनीय रूपांतर में प्रकट किए जाने के लिए दिशा-निर्देशों का प्रावधान है। किसी भी व्यापार सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है। समर्थक घरेलू उत्पादक ने उत्तरदाता को कोई संगत सूचना नहीं दी है।
- ग. याचिकाकर्ता ने पाटनरोधी करार के नियम 6 और तथा व्यापार सूचनाओं 2018 का 10, 2018 का 13 और 2018 का 14 के अनुसार गोपनीयता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

- घ. याचिकाकर्ता ने दिनांक 12 जून, 2020 के एक्सोटिक डेकोर प्रा. लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में माननीय सेस्टैट के हाल के फैसले के अनुसार प्रतिवादी को एक्सेल प्रपत्र में लेन-देनवार आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं।
- ड. याचिकाकर्ता और समर्थन करने वाले उद्योग की वार्षिक रिपोर्ट, गुणवत्ता नीति, बिन्नी नीति गोपनीय मानी गई है। प्राधिकारी ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 का उल्लंघन किया है। ईसी-फास्टनर्स (चीन) में पैनल की रिपोर्ट पर विश्वास किया गया है।
- च. प्रतिवादी के पास क्षति रहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने के लिए प्राधिकारी द्वारा की गई गणना के बारे में जानने का अधिकार है क्योंकि उसका निर्यातकों के मार्जिन पर प्रभाव पड़ेगा और वे उसके अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराने का अनुरोध करते हैं।

उ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

21. गोपनीयता के संबंध में जांच प्रक्रिया के दौरान आवेदक तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा संगत समझी गई सीमा तक जांच की गई है और निम्नलिखित रूप में उन्हें हल किया गया है।
22. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार, निरीक्षण के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्षों के अगोपनीय रूपांतर से युक्त सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया सूचना का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया।
23. जहां तक समर्थक उत्पादकों से सूचना का संबंध है, प्राधिकारी ने आवेदक घरेलू उद्योगकी सूचना के आधार पर वर्तमान जांच परिणाम रिकार्ड किए हैं और याचिका के समर्थन पर ध्यान नहीं दिया है। चूंकि, घरेलू उद्योग को क्षति समर्थक घरेलू उत्पादकों के आधार पर नहीं है, अतः इस तथ्य की संभावना कि उस घरेलू उत्पादक ने प्रपत्र के अनुसार पूरी तरह से सभी सूचना नहीं दी हो, वर्तमान निर्धारण और आवेदक घरेलू उद्योग के अधिकार को रद्द नहीं करता। प्राधिकारी ने इन समर्थक घरेलू उत्पादकों के निष्पादन का विश्लेषण करने की दृष्टि से ही समर्थक कंपनियों के लिए प्रपत्र निर्धारित किया है। ऐसी स्थिति में जहां समर्थक घरेलू उत्पादकों ने निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, प्राधिकारी ने उन अन्य घरेलू उत्पादकों को संभावित क्षति की जांच नहीं की है। तथापि, नियम 5(3) के अभिप्राय से "आधार" के संबंध में आवेदक का अधिकार कम नहीं किया जा सकता, यदि समर्थक घरेलू उत्पादक केवल कोई सूचना प्रदान किए बिना याचिका का केवल समर्थन करे।
24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है:

"गोपनीय सूचना: (1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उपनियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में निहित किसी बात को होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि गोपनीयता के लिए अनुरोध न्यायसंगत नहीं अथवा सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा इसको सामान्य तौर पर अथवा संक्षिप्त रूप में उसे प्रकट करने के लिए अनिच्छुक हो, तो ऐसी सूचना की उपेक्षा की जा सकती है।

25. जहां तक सूचना की गोपनीयता के संबंध में शर्तों का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और उस सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं की गई है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं। प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराया। घरेलू उद्योग के आयातों, निष्पादन मानदंडों और क्षति मानदंडों से संबंधित सूचना सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराई गई है। व्यापार संवेदी सूचना को परिपाठी के अनुसार गोपनीय रखा गया है।
26. इस तर्क के संबंध में कि लेन-देनवार से लेन-देनवार आयातों की ऐक्सल फाइल के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया था, आयात संबंधी आंकड़ों को प्राप्त करने और उसे साझा करने की प्रक्रिया दिनांक 15 मार्च, 2018 की व्यापार सूचना 07/2018 में निर्धारित की गई है। इसमें यह प्रावधान है कि (i) घरेलू उद्योग द्वारा विश्वास किए गए अलग-अलग आयात आंकड़ों को हार्ड कॉफी में साझा किया जा सकता है और (ii) हितबद्ध पक्षकार डीजीसीआईएंडएस लेन-देनवार आयात आंकड़ों द्वारा अपरिष्कृत लेन-देन प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी से अधिकरण की मांग कर सकते हैं। अलग-अलग किए गए आयात आंकड़ों की हार्ड कॉफी हितबद्ध पक्षकारों को निर्धारित प्रपत्र के अनुसार घोषणा/वचन-पत्र के आधार पर सुगम बनाया गया था। हितबद्ध पक्षकारों जिन्होंने डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़ों को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया था और व्यापार सूचना 07/2018 के अनुसार वचन-पत्र दिया था, को भी डीजीसीआईएंडएस से ऐक्सल फाइल में आयात आंकड़े प्राप्त करने के लिए अधिकरण दिया गया था। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि अब लागू की जा रही प्रक्रिया सभी पक्षकारों और जांचों के लिए निरंतर, एक जैसी है और इन हितबद्ध पक्षकारों को अपने हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त अवसर देते हैं।

च. विविध अनुरोध

च.1 घरेलू उद्योग के विचार

27. आवेदक द्वारा विविध अनुरोधों के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. केवल 6 महीने और 10 दिन का अंतराल है और न कि 7 महीने का अंतराल है जिसे निर्यातक द्वारा गलत इरादे से आरोप लगाया गया है। घरेलू उद्योग ने दिनांक 22 नवंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 15/2018 के संदर्भ में जांच की अवधि के समाप्त होने की तिथि से 5 महीने पूर्व आवेदन प्रस्तुत किया है। इस प्रकार, यह याचिका समय पर दायर की गई थी।
- ख. मैनुअल में निर्धारित समय-सीमा केवल आंतरिक दिशा-निर्देश है और न कि सामूहिक अंतिम समय-सीमा है जिसे प्राधिकारी माफ कर सकते हैं और माफी के अधिकार का उल्लेख मैनुअल के अस्वीकरण में किया गया है।
- ग. दिनांक 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 9/2020-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली में हाल में किया गया संशोधन जांच की शुरुआत के बाद आया और कोई भी संशोधन उस स्थिति में बाद की स्थिति से अधिरोपित नहीं किया जा सकता है जब तक विशिष्ट रूप से इसका प्रावधान न किया गया हो।

च.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

28. आवेदक द्वारा घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

- क. जांच की शुरुआत की तिथि और जांच की अवधि के समाप्त होने की तिथि के बीच 7 महीने का अंतराल है। मैनुअल और दिनांक 2 फरवरी, 2020 की अधिसूचना सं. 9/2020-सीमा शुल्क (एनटी) के माध्यम से पाटनरोधी नियमावली में हाल में किया गया संशोधन के अनुसार यह एक स्थापित सिद्धांत है कि जांच की अवधि इसकी शुरुआत की तिथि को 6 महीने से पुरानी नहीं हो सकती है। यह अनुरोध किया जाता है।

कि जांच की ऐसी अप्रचलित अवधि बाजार की सही तस्वीकर को प्रकट करने में सक्षम नहीं होगी और इसके फलस्वरूप सही परिणाम नहीं आएगा।

उ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. जहां तक लंबी जांच की अवधि तथा जांच की शुरूआत की तारीख से उसकी समीपता से संबंधित अनुरोधों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस मामले के लिए चुनी गई जांच की अवधि जांच की शुरूआत के समय कानूनी स्थिति तथा प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई परिपाठी के अनुरूप है। यद्यपि, जांच की अवधि के अंत से यथासंभव समीपता के रूप में जांच की शुरूआत की तारीख रखने के लिए जांच की शुरूआत की तारीख और जांच की अवधि की समाप्ति के बीच समय अंतराल कम से कम करना वांछनीय होगा। तथापि, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच की शुरूआत की तारीख को छः माह से अधिक पुरानी हो। यह आवेदन पत्र प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमाओं के भीतर आवेदक द्वारा दायर किया गया था और इसीलिए प्राधिकारी के लिए जांच की शुरूआत के समय विद्यमान कानूनी प्रावधानों के कार्यठांचे के अंतर्गत उस पर विचार करना अपेक्षित था।
30. यह भी नोट किया जाता है कि नियमावली में दिनांक 2 फरवरी, 2020 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 9/2020-सीमा शुल्क (एन.टी.) द्वारा संशोधन किया गया है, जिसमें नियम 2(घक) तथा नियम 22 का स्पष्टीकरण निम्नलिखित प्रावधान शामिल करते हुए जोड़ा गया है:

"जांच की अवधि:-

- (i) जांच की शुरूआत की तारीख को छः माह पुरानी से अधिक नहीं होगी।
- (ii) बारह माह की अवधि के लिए होगी तथा लिखित में रिकार्ड किए जाने वाले कारणों से निर्दिष्ट प्राधिकारी न्यूनतम 6 माह अथवा अधिकतम 18 माह पर विचार कर सकते हैं।"

31. तथापि, यह नोट किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधन वर्तमान जांच की शुरूआत के बाद किए गए हैं।
32. इस जांच में प्राधिकारी द्वारा ली गई 15 माह की जांच की अवधि के संबंध में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान मामले में आवेदन पत्र 3 दिसंबर, 2019 को दायर किया गया था। प्राधिकारी मानते हैं कि जांच की अवधि सामान्यतया 12 माह की अवधि होनी चाहिए। तथापि, प्राधिकारी 12 माह से अधिक लंबी अवधि (15 से 18 माह) पर विचार कर सकते हैं, यदि यह पाया जाए कि उस लंबी अवधि में पूरा लेखांकन वर्ष शामिल है और यह दर्शाने वाले कोई विशेष तथ्य नहीं हैं कि जांच की अवधि के रूप में 15 अथवा 18 माह की लंबी अवधि का निर्धारण अनुपयुक्त होगा।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

33. धारा 9क(1)(ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है:
- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
 - (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
 - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा उपधारा- (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्धम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

(ब) परंतु यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

छ.1 घरेलू उद्योग के विचार

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में आवेदक द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. चीन जन.गण. को पूर्व मामलों में प्राधिकारी द्वारा ली गई स्थिति और अन्य देशों में जांचकर्ता प्राधिकारियों द्वारा ली गई स्थिति के अनुरूप गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए।
- ख. चीनी उत्पादकों की लागत और कीमत पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विश्वास नहीं किया जा सकता और तदनुसार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा के प्रावधानों के 7 अनुसार किया जाना चाहिए।
- ग. संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन मुख्य रूप से चीन जन.गण. और भारत में किया जाता है। सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा संरचित मूल्य के आधार पर नहीं किया जा सकता है। आवेदक ने प्रशासनिक और बिक्री खर्च तथा लाभ की उचित राशि जोड़ने के साथ भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है।
- घ. प्रारंभिक जांच परिणामों में निर्धारित पाटन मार्जिन को कम बताया गया है। उत्तर देने वाले निर्यातकों को असहयोगी के रूप में माना जाना चाहिए तथा तदनुसार उन्हें असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्धारित उच्चतम मार्जिन की अनुमति दी जानी चाहिए। घरेलू उद्योग पर पाटन का प्रभाव बहुत अधिक है।
- ड. चीन के उत्पादकों ने एमईटी प्रश्नावली भी प्रस्तुत नहीं की है और उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों को यह हक नहीं है कि उन्हें अलग-अलग सामान्य मूल्य दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह स्थापित नहीं किया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण उनके अपने आंकड़ों के आधार पर किया जा सकता है।
- च. प्राधिकारी केवल निर्यात कीमत के निर्धारण के लिए अपने आंकड़ों पर विचार कर सकते हैं, वह भी तब जब वे सभी अर्थों में पूर्ण हों। आवेदक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे उत्तर देने वाले निर्यातकों में से प्रत्येक के लिए निर्यात कीमत की फिर से जांच करें और उसका निर्धारण करें।
- छ. सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर तय किया गया है जो बहुत अधिक व्यापार संवेदनशील सूचना है, जिसका प्रकटन प्रतिस्पर्धियों और उपभोक्ताओं को बहुत अधिक प्रतिस्पर्धी लाभ देगा और जो आवेदक के हित को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
- ज. चीन के उत्पादक पूरे विश्व में पाटन कर रहे हैं और प्राधिकारी उन्हें विश्व के शेष देशों को निर्यातों का पूर्ण बीजकावार ब्यौरा उपलब्ध कराने तथा तीसरे देश से निर्यातों में पाटन मार्जिन का निर्धारण करें।

छ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

35. आवेदक द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. पाटन मार्जिन का निर्धारण प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ख. सामान्य मूल्य के परिकलन में प्रत्येक लागत कारक के व्यवहार का विश्लेषण पाटन मार्जिन के परिकलन के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह पाटनरोधी कानून में पारदर्शिता के प्रावधानों के विरुद्ध है।
- ग. प्राधिकारी द्वारा परिकलित सामान्य मूल्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि प्राधिकारी को सर्वप्रथम सामान्य मूल्य तय करने के पूर्व पहली दो पद्धतियों का उपयोग करना चाहिए था। शेनयांग मितसुशिला एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. एवं अन्य (2005) 3 एससीसी 39 तथा चीन जन.गण. के विरुद्ध यूरोपीय कमीशन के पाटनरोधी मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विश्वास किया गया है।

36. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार दावे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है। यह अनुरोध किया गया है कि निर्यात कीमत, पहुँच मूल्य और पाटन मार्जिन प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में वास्तविक आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1 सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण

चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति

37. "जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता, 1994 ("पाटनरोधी समझौता") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन पर समझौता तथा एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे:

- (क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ सम्भाली से तुलना करने में आधारित नहीं है:
- (i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।
- (ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सम्भाल अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।
- (ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजस्वहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजस्वहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।
- (ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।
- (घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii)में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गया है, तथापि अभिगम नयाचार के 15(क)(i) के तहत दायित्वों के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अंतर्गत प्रावधान बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के स्तर का दावा करने के संबंध में पूरक प्रश्नावली में दी जाने वाली सूचना/आंकड़ों के माध्यम से पूरा किए जाने के लिए नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्धारित मानदंड की अपेक्षा है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्तरदाता उत्पादक तथा निर्यातक ने पूरक प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, अतः सामान्य मूल्य का परिकलन नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।
39. तदनुसार, संबद्ध देश से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत निम्नलिखित रूप में निर्धारित की गई है।

चीन जन. गण. में सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण

40. चूंकि, चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के लिए पूरक प्रश्नावली के उत्तर दायर नहीं किए हैं, अतः नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है:

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य, मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समायानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।”

41. नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित किए गए अनुसार, अन्य पद्धतियों के संबंध में, रिकार्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने “उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए यदि आवश्यक हो तो विधिवत समायोजित समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से प्रदत्त अथवा देय कीमत सहित किसी अन्य उपयुक्त आधार पर” पद्धति पर विचार कर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है। अतः प्राधिकारी ने उपयुक्त लाभ को जोड़कर बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों सहित विधिवत समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य अनंतिम रूप से निर्मित किया है। तदनुसार, चीनी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए इस प्रकार निर्धारित निर्मित सामान्य मूल्य निम्नलिखित पाठन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।
42. इस तर्क के संबंध में कि सामान्य मूल्य का निर्धारण सामान्य मूल्य तय करने के पूर्व पहली दो पद्धतियों का उपयोग करने के बाद किया जाना चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन मुख्य रूप से भारत और चीन जन.गण. में किया जाता है। इस तर्क की जांच की गई और यह नोट किया जाता है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।
43. सामान्य मूल्य के परिकलन को प्रकट किए जाने के संबंध में इस तर्क के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य भारत में उत्पादन की लागत जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च, उचित लाभ को जोड़ने सहित विधिवत् समायोजित आधार पर की गई है और उसे व्यापार संवेदनशील सूचना के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से निर्धारित संरचित सामान्य मूल्य का उल्लेख पाठन मार्जिन तालिका में किया गया है।

निर्यात कीमत का निर्धारण

44. मैसर्स शंघ्यु जिंकिसन फार्मास्युटिकल कं. लि. चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और संबद्ध कंपनी अर्थात् मैसर्स झेजियांग जिंकिसन फार्मास्युटिकल इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. (निर्यातक) के माध्यम से भारत को उत्पाद का निर्यात किया है। उत्तर प्राप्त होने के बाद सहयोगी उत्पादक और निर्यातक को कमियों के उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए कमी वाला पत्र भेजा गया था। सहयोगी उत्पादक और निर्यातक ने कमियों से संबंधित उत्तर प्रस्तुत कर दिए हैं तथा उत्तर की जांच की गई है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स शंघ्यु जिंकिसन फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण. ने संबद्ध कंपनी अर्थात् मैसर्स झेजियांग जिंकिसन फार्मास्युटिकल इम्पॉर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि. (निर्यातक) के माध्यम से *** मी. टन संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के व्यौरों की जांच की है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, सारसंभाल एवं सीमा शुल्क प्रभार, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट वापसी के निमित्त समायोजन की जांच संभव सीमा तक डेस्क सत्यापन के माध्यम से की गई है और तदनुसार, उत्पादक अर्थात् मैसर्स शंघ्यु जिंकिसन फार्मास्युटिकल कं. लि. के कारखानागत स्तर पर विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है और उसे पाठन मार्जिन तालिका में दर्शाया गया है।

मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण.

45. मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों के व्यौरे दिए हैं। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिशिष्ट 3ख और 3ग उनके मामले में लागू नहीं है क्योंकि संबद्ध भारतीय ग्राहकों को कोई बिक्रियां नहीं हैं और उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने व्यापारी कंपनी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण. ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** मी. टन संबद्ध सामानों का सीधे ही निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार और गैर वापसी योग्य वैट के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने सूचना के सत्यापन के अध्यधीन प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के व्यौरों पर विश्वास किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, सारसंभाल एवं सीमा शुल्क प्रभार, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजन के साथ निर्यात कीमत की जांच संभव सीमा तक डेस्क के सत्यापन के माध्यम से की गई है और तदनुसार उत्पादक मैसर्स झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि. के एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाठन तालिका में किया गया है।

मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं., चीन जन. गण.

46. मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण. में संबद्ध सामानों का उत्पादक है और उसने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को सीधे ही संबद्ध सामानों का निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर के परिशिष्ट 3क में भारत को संबद्ध सामानों के निर्यातों के व्यौरे दिए हैं। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिशिष्ट 3ख और 3ग उनके मामले में लागू नहीं है क्योंकि संबद्ध भारतीय ग्राहकों को कोई बिक्रियां नहीं हैं और उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने व्यापारी कंपनी के माध्यम से भारत को संबद्ध सामानों का निर्यात नहीं किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि., चीन जन. गण. ने भारत में असंबद्ध ग्राहकों को *** मी. टन संबद्ध सामानों का सीधे ही निर्यात किया है। उत्तरदाता उत्पादक/निर्यातक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, पत्तन एवं अन्य संबद्ध व्यय, ऋण लागत, बैंक प्रभार और गैर वापसी योग्य वैट के निमित्त समायोजनों का दावा किया है जिनकी प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई है। प्राधिकारी ने सूचना के सत्यापन के अध्यधीन प्राथमिक जांच परिणामों के प्रयोजन के लिए उत्पादक/निर्यातक द्वारा दायर प्रश्नावली के उत्तर में दिए गए निर्यातों के व्यौरों पर

विश्वास किया है। अंतर्देशीय भाड़ा, समुद्री भाड़ा, सार संभाल एवं सीमा शुल्क प्रभार, बीमा, कमीशन, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार और वैट के कारण समायोजन का दावा किया है। इन समायोजन के साथ निर्यात कीमत की जांच संभव सीमा तक डेस्क के सत्यापन के माध्यम से की गई है और तदनुसार उत्पादक मैसर्स झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. के एक्स-फैक्टरी स्तर पर निर्यात कीमत का निर्धारण किया गया है जिसका उल्लेख नीचे दी गई पाठन तालिका में किया गया है।

चीन जन. गण. से सभी अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत

47. चीन जन. गण. से अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत उस देश के सहयोगी निर्यातकों के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है।

छ.3.2 पाठन मार्जिन

48. ऊपर निर्धारित किए गए अनुसार सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए पाठन मार्जिन निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

पाठन मार्जिन तालिका

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य/ सीएनबी (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	पाठन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	पाठन मार्जिन%	पाठन मार्जिन रेज
चीन जन. गण.	शंघाय जिंकिसन फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	20-40
	झेजियांग लंघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि..	***	***	***	***	0-20
	झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-20
	अन्य	***	***	***	***	20-40

ज. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

ज.1 घरेलू उद्योग के विचार

49. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:

- क. आयातों की मात्रा ने पूर्ण दृष्टि से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के संबंध में काफी वृद्धि दर्शाई है।
- ख. संबद्ध देश से आयात पूरी क्षति अवधि में बढ़े हैं।
- ग. यद्यपि, आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उत्पादकों के बाजार हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई है।
- घ. आयात भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों की काफी कटौती कर रहे हैं।
- पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों का ह्रास किया है।
- ड. पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव पड़ा है।

- च. घरेलू उद्योग ने भारत में और वैश्विक रूप से उत्पाद के लिए वर्तमान एवं संभावित मांग की दृष्टि से उत्पाद के लिए अपनी क्षमता बढ़ाई। तथापि, घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में मांग में वृद्धि के बावजूद क्षति की अवधि में गिरावट आई है।
- छ. बढ़ते हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग में अतिरिक्त क्षमता भारी मात्रा में अनुपयुक्त रही है जिसके परिणामस्वरूप क्षति की अवधि में क्षमता उपयोग में गिरावट आई।
- ज. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि में हानियां हो रही हैं।
- झ. घरेलू उद्योग को नकद हानियां तथा जांच की अवधि में नियोजित पूँजी पर नकारात्मक आय हो रही है।
- ज. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में देश में पर्याप्त क्षमताओं की मौजूदगी के बावजूद, क्षति की अवधि में गिरावट आई।
- ट. मालसूची ने पूरी क्षति अवधि में काफी वृद्धि दर्शाई है। जांच की अवधि में मालसूची आधार वर्ष में मालसूची के 4.2 गुना थी।
- ठ. उत्पादकता में घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमताओं में अभिवृद्धि के बावजूद पूर्ण दृष्टि से तथा सापेक्ष दृष्टि से गिरावट आई है।
- ड. आवेदक कुछ अन्य सामानों का उत्पादन भी करता है और इसीलिए रोजगार तथा मजदूरी पूर्णतः संबद्ध सामानों के निष्पादन पर निर्भर नहीं है।
- ढ. पाठन मार्जिन केवल न्यूनतम से अधिक ही नहीं है बल्कि काफी भी है। घरेलू उद्योग पर पाठन का प्रभाव प्रतिकूल है।
- ण. उत्पादन ,बिक्री, बाजार हिस्सा ,लाभनिवेश पर आय, नकद लाभ आदि जैसे अधिकतर मानदंडों के , संदर्भ में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल है।
- त. घरेलू उद्योग के कार्यों की स्थिति को देखते हुए, जहां उत्पाद का विनिर्माण और बिक्री पिछले कुछ वर्षों में विद्यमान पाठन के कारण निरंतर निष्पादन नहीं कर रही है, काफी नए निवेशों की कल्पना नहीं की जा सकती।
- थ. इन आंकड़ों में कोई सटीकता नहीं है। हितबद्ध पक्षकार ने आंकड़ों का विश्लेषण नहीं किया है।
- द. आवेदक भारत में प्रमुख द्वा निर्माताओं में से एक है और यह लगभग 50 उत्पादों के उत्पादन वाले अनेक बल्क ड्रग्स (एपीआई) का उत्पादन करता है। काफी संख्या में उत्पादों में, भारत और चीन जन.गण. वैश्विक स्तर पर एकमात्र उत्पादक हैं। चीन के उत्पादक चाहते हैं कि वैश्विक एकाधिकार प्राप्त करने के लिए भारत में उत्पादन समाप्त हो जाए।
- ध. वार्षिक रिपोर्ट में लाभ विचाराधीन उत्पाद को नहीं दर्शाता है। 7-10 प्रतिशत कर-पूर्व लाभ होना बहुत अधिक उच्च लाभ के रूप में नहीं माना जा सकता है।
- न. प्राधिकारी सभी आंकड़ों का सत्यापन करने के बाद तथा कुल मात्राओं और आयात कीमतों पर विचार करने के लिए पाठनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं और वर्तमान में, आरती को केवल एक उत्पाद-ओफलोसाक्सिन पर ही पाठनरोधी शुल्क लगता है। इस प्रकार, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के दावे का कोई आधार नहीं है और यह राष्ट्र के हित में नहीं है।
- प. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है। घरेलू उद्योग के समग्र कार्य-निष्पादन पर पाटित आयातों के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
- फ. पाठनरोधी नियमावली के अंतर्गत कुल में से पाटित आयातों के 3 प्रतिशत को बहुत अधिक के रूप में माना गया है और प्रभावित घरेलू उद्योग पाठनरोधी कानून के अंतर्गत राहत की मांग कर सकते हैं और वर्तमान मामले में, संबद्ध देश से आयात इस नियमावली के अंतर्गत माने गए प्रतिशत की तुलना में बहुत अधिक हृद तक मांग का प्रतिशत है। संबद्ध देश से आयातों में क्षति की अवधि के दौरान लगभग 28 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जिसे कम के रूप में नहीं माना जा सकता है।

- ब. इसका कोई आधार नहीं है कि निर्यात बिक्री कीमत घरेलू बिक्री कीमत की तुलना में कम है। घरेलू उद्योग ने अपने घरेलू कार्य-निष्पादन के आधार पर इसके दौरान उठाई गई क्षति का दावा किया है। निर्यातों में संभावित प्रतिकूल लाभ घरेलू प्रचालनों में लाभ को प्रभावित नहीं कर सकता है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग अपनी इच्छा से अथवा अधिमान्यता से नहीं बल्कि पाटन कार्य-पद्धतियों द्वारा उत्पन्न बाध्यता के कारण आदर्शतम से कम कीमतों पर निर्यात कर रहा है।
- भ. निर्यातक इन आंकड़ों को नहीं मानने की कोशिश कर रहे हैं जिनका सत्यापन और जिन पर विचार प्राधिकारी द्वारा किया गया है। मालसूची में वृद्धि को प्राधिकारी द्वारा सही माना गया है। जहां तक रोजगार और मजदूरी का प्रश्न है, घरेलू उद्योग ने इन आधारों पर क्षति का दावा नहीं किया है। क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर सूचना उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि क्षति संबंधी सभी मानदंडों में क्षति दर्शाई जाए।
- म. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में गिरावट नहीं आई है और घरेलू उद्योग के बारे में इस प्रकार के वक्तव्य देने के लिए हितबद्ध पक्षकार के पास कोई आधार नहीं है।
- य. घरेलू उद्योग ने भारतीय मांग को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का विस्तार किया और क्षमताओं में विस्तार के बावजूद आवेदक को लाभ हुआ था।
- कक. ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 (“डीपीसीओ”) के अंतर्गत लगाई गई उच्चतम कीमत निर्माण के लिए है और न कि एपीआई अथवा बल्कि ड्रग्स के लिए है।
- खख. कोरोना वायरस के कारण आम लोगों के स्वास्थ्य की आपातकाल का मुद्दा पाटन के मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगाने को न्यायोचित ठहराता है। निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे उत्पादों के लिए इस देश को चीन के उत्पादकों की दया पर नहीं छोड़ देना चाहिए। घरेलू उद्योग बिना किसी रुकावट के इस महामारी के समय भी इन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति कर रहा है।
- गग. एक रोगी का उपचार करने के लिए विचाराधीन उत्पाद की लागत सात दिनों की अवधि के दौरान एक रोगी द्वारा 5.81 ग्राम उत्पाद की खपत और 2000 रु. प्रति किंवा. की बिक्री कीमत पर विचार करते हुए बहुत कम 12 रु. है। इस प्रकार निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया प्रति रोगी प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करें। यह बाजार में एक कप चाय की न्यूनतम कीमत भी नहीं होगी।
- घघ. व्यापक जनहित गतिशील और अर्थक्षम घरेलू उद्योग के होने की मांग करता है। शुल्क लगाना क्षतिग्रस्त घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं में संतुलन की मांग करते समय भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के लिए है। प्राधिकारी को यह जांच करने की आवश्यकता है कि जो देश के सामान्य हित में है।
- ड.ड. वर्तमान मामला पाटन मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक सही मामला है क्योंकि चीन के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति में कार्य कर रहे हैं और क्षति मार्जिन घरेलू उद्योग को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
- चच. पाटन और क्षति मार्जिन जिसके बारे में दावा आवेदक द्वारा किया गया है, बहुत अधिक था जबकि अनंतिम जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन दावा किए गए मार्जिन से बहुत कमतर है। निर्धारित एनआईपी अनुचित रूप से कम है जिसके फलस्वरूप बहुत कम मार्जिन है और इस पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है।
- छछ. कोई भी देश विश्व में उस तरीके से कमतर शुल्क नियम का पालन नहीं करता है जिस तरीके से इसे भारत में लागू किया जाता है और घरेलू उद्योग को वास्तव में “सबसे कम शुल्क नियम” के आधार पर शुल्क प्राप्त हुआ है।

ज.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

50. क्षति और कारणात्मक संपर्क के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध संक्षेप में नीचे दिए गए हैं:
- क. विभिन्न आर्थिक मानदंडों के लिए दिए गए आंकड़े गलत हैं क्योंकि ये तत्व जांच की अवधि तथा वार्षिकीकृत जांच की अवधि के लिए समान हैं। यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत स्थापित सटीकता और पर्याप्तता की जांच को पूरा नहीं किया और इसमें व्यापार सूचना 2018 का 15 की जांच सूची के अनुसार अनेक कमियां हैं।
 - ख. याचिका पर विश्वास नहीं किया जा सकता और आवेदक द्वारा दिए गए गलत आंकड़ों के कारण हुई क्षति के संबंध में अनुरोध नहीं किए जा सकते। प्राधिकारी को चाहिए कि वे याचिकाकर्ताओं से कहे कि वे अपेक्षित अनुरोध करने के लिए संशोधित याचिका दें।
 - ग. आरती ड्रग्स लि. व्यापार उपचार उपाय (टीआरएम) का एक नियमित प्रयोक्ता है और उसे कोई क्षति नहीं हो रही है।
 - घ. वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक अत्यधिक लाभ कमा रहा है और बहुत अच्छा लाभांश दे रहा है। कई उत्पादों में साथ-साथ क्षति होने पर लाभप्रदता का यह उच्च स्तर दर्शाता है कि आवेदक का इन उपायों के माध्यम से स्वयं के लिए एक अनुचित बाजार स्तर सूजित करने का इरादा है।
 - ङ. घरेलू उद्योग को संबद्ध आयातों के कारण वास्तविक क्षति नहीं हो रही है।
 - च. आयातों में केवल 28 प्रतिशत की वृद्धि आयातों में काफी वृद्धि, विशेष रूप से घरेलू उत्पादकों द्वारा इतने भारी उत्पादन के सामने निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
 - छ. संबद्ध आयातों का भारत में बहुत ही छोटा बाजार हिस्सा है।
 - ज. उत्पादन और खपत के संबंध में आयातों की प्रवृत्ति भ्रामक है।
 - झ. संबद्ध देश से आयातों के कारण कोई कीमत न्यूनीकरण अथवा ह्रास नहीं हुआ। घरेलू बिक्री से बिक्री वसूली निर्यात बिक्री से बिक्री वसूली की अपेक्षा काफी अधिक है।
 - ञ. आयात कीमत भी उत्पादन लागत के अनुरूप रही।
 - ट. घरेलू उद्योग की कम बिक्री वसूली और संबद्ध आयातों के बीच कोई कारणात्मक संपर्क नहीं है। लागत और घरेलू बिक्री से बिक्री वसूली के बीच अंतराल अधिक नहीं है।
 - ठ. संबद्ध सामानों की कीमतें वैश्विक रूप से कम हैं और वे केवल भारत में ही नहीं जो संबद्ध देश से आयातों द्वारा डाले गए किसी कीमत दबाव के कारण हो सके।
 - ड. घरेलू उद्योग के संगत आर्थिक मानदंडों में सुधार है।
 - ढ. घरेलू बिक्री में गिरावट 2017-में मांग में भारी गिरावट तथा घरेलू उद्योग द्वारा संचालित व्यापारिक 18 निर्णयों के कारण है।
 - ण. अन्य उत्पादक 2017-18 में मांग में गिरावट के बावजूद बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम रहे हैं।
 - त. 4 गुना तक बढ़ी हुई मालसूची के दावे गलत और अविश्वसनीय प्रतीत होते हैं क्योंकि उत्पादन में गिरावट तथा की जा रही कुल बिक्री में वृद्धि हुई है।
 - थ. कर्मचारियों के संदर्भ में कोई क्षति नहीं है क्योंकि आधार वर्ष से कर्मचारियों की वृद्धि हुई है।
 - द. प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट को मांग में गिरावट तथा घरेलू उद्योग द्वारा की गई क्षमता की वृद्धि से संबंधित आशंकित व्यापारिक निर्णयों के कारण उत्पादन में कमी से नहीं जोड़ा जा सकता।
 - ध. यह मानते हुए कि लागत कीमत और बिक्री कीमत के बीच मार्जिन बहुत कम है, वर्ष 2017-18 और जांच की अवधि में घरेलू उद्योग के लिए लाभ में गहरा उछाल है।

- न. पीबीटी पीबीआईटी के बीच अंतर व्याज लागतों का अंतर है। दोनों के बीच अंतराल व्यापक हो रहा है, परंतु वह व्याज लागत में नहीं दर्शाया गया है।
- प. क्षमता में वृद्धि तथा नियोजित पूँजी में गिरावट से भी कंपनी द्वारा अर्जित आय प्रभावित हुई है।
- फ. प्राधिकारी को इस बात की आवश्यकता है कि वे घरेलू उद्योग द्वारा किए गए लाभप्रदता के दावों का सत्यापन करें क्योंकि ये आंकड़े सही प्रतीत नहीं होते।
- ब. यदि कोई क्षति है तो वह संबद्ध आयातों को छोड़कर अन्य स्रोतों के कारण हैग में गिरावट के यथा मां, समय क्षमता में वृद्धि तथा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए उत्पाद की लागतों में काफी वृद्धि से भारी हानियां हुई हैं जिसने जांच की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता प्रभावित की।
- भ. पीबीटी और पीबीआईटी में अंतर व्याज लागतों की प्रवृत्ति से मेल नहीं खाता।
- म. हो सकता है कि क्षमता विस्तार के कारण उच्च व्याज लागतें छिपाई जा रही हैं।
- य. क्षति स्व प्रभावित है और संबद्ध आयातों के कारण नहीं हो सकती।
- कक. उच्च लागतों तथा घरेलू उद्योग की कम निर्यात कीमत के कारण भारी हानियां हैं। निर्यात कीमत और निर्यातों के लिए उत्पादन लागत के बीच भारी अंतर है।
- खख. घरेलू उद्योग लागत दक्ष नहीं है, जैसा कि कीमत दबाव से दर्शाया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका सामना कर रहा है। संबद्ध आयातों के लिए घरेलू उद्योग की अदक्षता का भार वहन करना अनुचित होगा।
- गग. आयातों और लाभ के संदर्भ में घरेलू उद्योग के निष्पादन के बीच कारणात्मक संपर्क टूट गया है। क्षति की अवधि के दौरान कीमत कटौती स्थिर रही है, परंतु लाभ में काफी मार्जिन तक गिरावट आई है।
- घघ. प्राधिकारी को पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं करनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि पाटन, क्षति और कारणात्मक संपर्क का कोई साक्ष्य नहीं है।
- डड. कोरोना वायरस फैलने के कारण एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति है और सिप्रोफ्लोक्सासिन एन्सीएल विभिन्न संक्रमणों तथा निमोनिया से बचाव के लिए व्यापक रूप से फैले और घातक कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रयुक्त औषधि का एक मुख्य रासायनिक संघटक है।
- चच. उन आयातों पर शुल्क लगाना जनहित में नहीं होगा जो देश की जनता के जीवन को बचा सकते हैं। घरेलू उद्योग ने कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं और भारतीय जनसमूह के लिए यह औषधि अनुपलब्ध हो सकती है।
- छछ. इस महामारी के कारण, घरेलू उद्योग चीन से पर्याप्त कच्ची सामग्री खरीदने में असमर्थ है जिससे घरेलू उद्योग को झटका लग रहा है। अतः पाटनरोधी शुल्क लगाना भारत की स्थानीय निचले स्तर की फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा।
- जज. आरंभिक शुल्क को लगाना आवश्यक नहीं था क्योंकि कोई क्षति और संबद्ध देश से आयातों के बीच कोई कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है।
- झझ. चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से “पोलिस्टर स्टेपल फाइबर” के संबंध में की गई जांच पर विश्वास किया गया है जिसमें प्राधिकारी ने इस जांच को समाप्त कर दिया था क्योंकि भारत में अन्य उत्पादक अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे।
- जज. घरेलू उद्योग को क्षति गलत तरीके से दर्शाया गया है और उसकी पुष्टि समर्थक साक्ष्य से नहीं की गई है क्योंकि क्षति के विशेषण की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों में बहुत अधिक लाभ दर्ज किया गया और उत्पादन तथा बिक्री में बहुत अधिक हद तक वृद्धि हुई है।
- टट. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के अनुसरण में क्षति संबंधी सभी मानदंडों पर विचार नहीं किया है और यह विशेषण विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 3.4 में दी गई आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है जो आवेदक को न केवल वास्तविक गिरावट को सिद्ध करने का निदेश देता है बल्कि संभावित गिरावट के प्रभावों को भी अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।

- ठ. कम कीमत पर बिक्री नहीं हुई है क्योंकि एनआईपी पहुंच मूल्य से कमतर होगी। कच्चे माल की खरीद के संबंध में कच्चे माल की अकार्य-अमता को भी वार्षिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है।
- डड. प्राधिकारी द्वारा परिकलित एनआईपी घरेलू उद्योग की (क) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्चे माल की खरीद करने और (ख) भारत में संबद्ध वस्तुओं के सभी उत्पादकों ने आदर्शतम संसाधनों (सर्वोत्तम उत्पादन उपयोगिता अनुपात) का उपयोग करते हुए इन वस्तुओं का निर्माण करने में अक्षमता की उपेक्षा करती है। एनआईपी की यह गणना रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी एवं अन्य में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय से मेल नहीं खाता है।
- ढड. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत की फिर से गणना न्यूलैंड लेबोरेट्रीज लिमिटेड और डा.रेडीज लेबोरेट्रीज सहित भारत में कम से कम तीन उत्पादकों के निर्माण की लागत के आधार पर की जा सकती है क्योंकि ये कंपनियां अक्षम नहीं हैं।
- णण. समर्थक उद्योग को क्षति के विश्लेषण की समग्र अवधि और जांच की अवधि के दौरान असाधारण रूप से बहुत अधिक लाभ हो रहा है।
- तत. चूंकि यह क्षति स्वयं के कारण हुई है और बिक्री के मूल्य में वृद्धि हुई है अतः कच्चे माल की स्थिर लागत और समर्थक उद्योग की बढ़ी हुई लाभप्रदता यह दर्शाती है कि घरेलू उद्योग की आंतरिक अक्षमताएं हैं।

ज.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

51. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में "... पाठित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ..." घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाठित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाठित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूप जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाठित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, अमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
52. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में लिया है और उसका विश्लेषण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करते हुए है। घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर चर्चा वास्तव में किए गए क्षति विश्लेषण में किया गया है।

ज.3.1 पाठित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. मांग का मूल्यांकन/स्पष्ट खपत

53. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत पर भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयातों की मात्रा के रूप में विचार किया है।

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	मी. टन	908	810	648	1,007	806
समर्थकों की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
संबद्ध देश से कुल आयात	मी. टन	117	171	217	347	278
अन्य देशों से आयात	मी. टन	-	-	-	8	6
कुल मांग/खपत	मी. टन	2,730	2,837	2,475	3,444	2,755

54. यह देखा जाता है कि यद्यपि विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में 2017-18 में गिरावट आई, तथापि, जांच की अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई है। आधार वर्ष की तुलना में संबद्ध सामानों के लिए मांग में आंशिक वृद्धि हुई है।

ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा

55. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में, प्राधिकारी के लिए इस पर विचार करना अपेक्षित है कि संबद्ध देश से पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संबंध में पाटित आयातों में काफी वृद्धि हुई है। अति विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, प्राधिकारी ने डीजीसीआईएंडएस से लिए गए लेन-देन वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की मात्रा का विश्लेषण निम्नलिखित रूप में किया गया है:

आयात की मात्रा	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
संबद्ध देश— चीन जन.गण.	मी. टन	117	171	217	347	278
अन्य देश	मी. टन	-	-	-	8	6
कुल आयात	मी. टन	117	171	217	355	284
कुल मांग/खपत	मी. टन	2,730	2,837	2,475	3,444	2,755
उत्पादन	मी. टन	3,236	3,530	3,001	3,835	3,068
के संबंध में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात						
कुल भारतीय उत्पादन	%	3.62%	4.85%	7.23%	9.06%	9.06%
मांग/खपत	%	4.29%	6.04%	8.77%	10.09%	10.09%

56. यह नोट किया जाता है कि:

- क. पाटित आयातों की मात्रा अति की अवधि में पूर्ण दृष्टि से काफी बढ़ी है।
 ख. आयातों ने घरेलू उत्पादन और खपत के संबंध में काफी वृद्धि दर्शाई है।

ज.3.2 पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

57. नियमावली के अनुबंध-II (ii) के अनुसार, कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा काफी कीमत कटौती की गई है अथवा उन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमत रोकने के लिए अन्यथा है अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो कि अन्यथा काफी मात्रा तक हुई होती।

क. कीमत में कटौती

58. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुँच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत का परिकलन करते समय सभी कर, छूटें, रियायतें और कमीशन को घटा दिया गया है और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली पर पाटित आयातों के पहुँच मूल्य के साथ तुलना के लिए विचार किया गया है। तदनुसार, संबद्ध देश के पाटित आयातों का कटौती प्रभाव निम्नलिखित रूप में निकलता है:

कीमत में कटौती

विवरण	यूनिट	चीन जन.गण			जांच की अवधि(वार्षिकीकृत)
		2015-16	2016-17	2017-18	
आयातों की पहुँच कीमत	रु./कि. ग्रा.	1,743	1,295	1,447	1,819
निवल बिक्री कीमत	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि. ग्रा.	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	रेंज	(0-10)	0-10	0-10	0-10

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम थीं। इसके अतिरिक्त, आंशिक कीमत कठोरी विदेशी उत्पादकों और घरेलू उद्योग के बीच सछत प्रतिस्पर्धा का संकेत है।

ख. कीमत हास एवं न्यूनीकरण

60. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का हास कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों का काफी मात्रा तक न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में की गई थी:

कीमत हास एवं न्यूनीकरण

	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
बिक्रियों की लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	97	127
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	93	115
पहुँच कीमत-चीन जन.गण	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***
सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	100	74	83	104

61. यह देखा जाता है कि यद्यपि संबद्ध देश से आयातों की पहुँच कीमत वर्ष 2015-16 और 2016-17 में घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से अधिक थी, तथापि, इसमें उसके बाद बिक्री लागत से कम स्तर तक गिरावट आई। जांच की अवधि के दौरान, आयातों की पहुँच कीमत बिक्री लागत से काफी कम है। परिणामस्वरूप, यहां तक कि यद्यपि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में वृद्धि हुई है, तथापि यह वृद्धि उसकी अवधि के दौरान बिक्री लागत में वृद्धि से काफी कम है। इस प्रकार, आयातों ने कीमत वृद्धि रोकी है जो अन्यथा हुई होती। घरेलू उद्योग में संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत न्यूनीकरण हुआ है।

ग. कम कीमत पर बिक्री

62. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई कम कीमत पर बिक्री से क्षति की भी जांच की है। इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत की तुलना डीजीसीआईएंडएस के आयात आंकड़ों से प्राप्त आयातों की पहुँच कीमत से की गई है।

कम कीमत पर बिक्री		
विवरण	यूनिट	कम कीमत पर बिक्री
पहुँच कीमत	रु./कि. ग्रा.	***
क्षति रहित कीमत	रु./कि. ग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	रु./कि. ग्रा.	***
कम कीमत पर बिक्री	%	***
कम कीमत पर बिक्री	रेंज	0-20

63. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से कम था और इस प्रकार काफी कम कीमत पर बिक्री हो रही थी।

ज.3.3. घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

64. नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में समान उत्पाद के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की तथ्यपरक जांच शामिल होगी। इस प्रकार के उत्पादों का घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, नियमावली में आगे यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में समस्त संगत आर्थिक कारकों और तत्वों जिनका घरेलू उद्योग की हालत पर प्रभाव पड़ता हो, जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता उपयोग में

वास्तविक और संभावित गिरावट; वे कारक जो घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन कीमात्रा पर प्रभाव डालते हों; नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव का वस्तुप्रक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मानदंडों पर यहां नीचे चर्चा की गई है:

क. उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

65. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग निम्नलिखित हैं:

विवरण	यूआईएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
क्षमता	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	107	140	112
कुल उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	92	115	92
क्षमताउपयोग	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	85	82	82
घरेलू बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	89	71	111	89
निर्यात बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	118	102	134	107
कुल बिक्री	मी. टन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	83	119	96

66. यह देखा जाता है कि:

- क. घरेलू उद्योग ने क्षति की अवधि के दौरान अपनी क्षमता बढ़ाई है।
- ख. यद्यपि, घरेलू उद्योग की क्षमता बढ़ी, तथापि 2016-17 के बाद उसके उत्पादन में कमी हुई। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है।
- ग. घरेलू उद्योग की बिक्री में आधार वर्ष से लेकर 2017-18 में गिरावट आई है तथापि यहां तक कि वह वह 2015-16 में खपत से थोड़ी सी अधिक थी। यद्यपि जांच की अवधि में वृद्धि हुई है और मांग मात्रा से कम रही।

ख. मांग में बाजार हिस्सा

67. घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा और आयातों का बाजार हिस्सा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया था:

विवरण	यूआईएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि (वार्षिकीकृत)
घरेलू उद्योग की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88	79	88
समर्थकों की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	107	100
अन्य उत्पादकों की बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	104	98
संबद्ध देश से कुल आयात	%	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	225	250
अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-	-	-	100
कुल मांग/घरपत	%	***	***	***	***

68. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, तथापि घरेलू उद्योग के हिस्से में इस अवधि में गिरावट आई है। इसके अतिरिक्त, भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में भी समग्र रूप से गिरावट आई है। बाजार हिस्से में गिरावट क्षमता में वृद्धि के बावजूद है।

ग. मालसूची

69. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग में मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि
आरंभिक स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
अंतिम स्टॉक	मी.टन	***	***	***	***
औसत मालसूचियां	मी.टन	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	345	418

70. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची क्षति की अवधि में काफी बढ़ी है।

घ. लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ

71. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
बिक्री कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	93	115	115
लागत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	84	97	127	127
लाभ/हानि	रु./कि.ग्रा.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	86	(35)	(246)	(246)
लाभ/हानि	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	(25)	(273)	(219)
ब्याज पूर्व लाभ/हानि और कर	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	67	16	(72)	(57)
नकद लाभ	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	10	(128)	(103)
औसत नियोजित पूँजी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79	70	87	87
आरओसीई	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85	23	(66)	(66)

72. यह देखा जाता है कि:

- क. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में क्षति की अवधि में निरंतर गिरावट आई है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं।
- ख. इसी प्रकार नकद और निवेश पर आय में गिरावट आई है तथा वहि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक हो गए।

ड. रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी

73. क्षति की अवधि में रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी						
विवरण	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि	जांच की अवधि
					वास्तविक	वार्षिकीकृत
कर्मचारी	संख्या	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	101	102	102
प्रति दिन उत्पादकता	मी.टन/ दिन	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	92	92	92
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी. टन/सं.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	91	90	90
मजदूरी	लाख रु.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	108	159	127

74. यह देखा जाता है कि कर्मचारियों की संख्या क्षति की अवधि के दौरान लगभग उसी स्तर पर रही जबकि मजदूरी में वृद्धि हुई है। उत्पादन में कमी से उत्पादकता में गिरावट आई है।

च. वृद्धि

वृद्धि	यूनिट	2015-16	2016-17	2017-18	जांच की अवधि-वार्षिकीकृत
उत्पादन (मी. टन)	%	2.42	(10.47)	0.18	
घरेलू बिक्री मात्रा (मी. टन)	%	(10.75)	(19.99)	24.28	
क्षमता उपयोग	%	2.15	(15.17)	(2.89)	
बिक्रियों की लागत (रु./कि.ग्रा.)	%	(16.22)	15.69	30.82	
बिक्री कीमत (रु./कि. ग्रा.)	%	(16.15)	10.56	23.89	
लाभ/हानि (रु./कि. ग्रा.)	%	(14.04)	(141)	(606)	
नकद लाभ	%	(21.58)	(87.75)	(1,167.69)	
आरओआई	%	(1.88)	(7.56)	(10.89)	

75. उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि 2017-18 के दौरान नकारात्मक थी, यद्यपि जांच की अवधि में इनमें कुछ सीमा तक सुधार आया। तथापि, नियोजित पूँजी पर आय और नकद लाभ ने पूरी क्षति अवधि, विशेष रूप से जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शाई।

छ. पूँजी निवेश जुटाने की क्षमता

76. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग में कम क्षमता उपयोग और हानियां हो रही हैं। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग की नियोजित पूँजी पर आय नकारात्मक हो गई है। यह बताता है कि पूँजी निवेश जुटाने में आयात घरेलू उद्योग की क्षमता प्रभावित कर सकते हैं।

ज. पाटन का परिमाण

77. यह नोट किया जाता है कि भारत में संबद्ध सामानों का पाटन किया जा रहा है और पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

झ. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

78. संबद्ध देश से आयात की कीमतों, लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों जो घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं, आदि की जांच यह दर्शाती है कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुँच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के लिए निर्धारण हैं। वस्तुतः घरेलू उद्योग आयातों की कीमतों से मेल खा रहा है और लागतों में वृद्धि के अनुपात में अपनी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से संबद्ध सामानों की पहुँच कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर रही हैं।

79. जहां तक आंकड़ों की शुद्धता के संबंध में तर्कों का संबंध है, वर्तमान जांच परिणाम अनंतिम रूप से सत्यापित आंकड़ों के आधार पर रिकार्ड किए जा रहे हैं। इस तथ्य कि जांच की अवधि के लिए सूचीबद्ध आंकड़े और जांच की अवधि के लिए वार्षिकीकृत आंकड़े समान हैं, का अभिप्राय यह नहीं है कि अपनाए गए आंकड़े गलत हैं। चूंकि पूर्व वर्ष बारह की अवधि के हैं, जबकि जांच की अवधि 15 माह की अवधि की है, अतः सूची को उसे उपयुक्त रूप से दर्शाना अपेक्षित है।

80. प्राधिकारी ने उत्पादन लागत में वृद्धि के कारणों की जांच की। यह नोट किया जाता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि के लिए प्राथमिक कारण विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल एक प्रमुख कड़ी सामग्री में वृद्धि है।

81. जहां तक जनहित के तर्कों का संबंध है, यह उल्लेख किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन केवल पाटन की अंतिम परिपाठी को दूर करना है। घरेलू उद्योग को छोड़कर अंत में उपयोग पर प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क की मात्रा को प्रभावित किया है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टियों में से किसी ने भी अपने तर्क के समर्थन में कोई सबूत नहीं लाया है कि प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के लागू होने से देश के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

82. जहां तक वार्षिक रिपोर्ट में सूचित किए गए आवेदक के लाभ का संबंध है, यह नोट किया जाता है कि आवेदक एक बहु उत्पाद कंपनी है जिसके बहुसंख्य उत्पाद हैं। वार्षिक रिपोर्ट में सूचित लाभ विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग का निष्पादन नहीं दर्शाते।

83. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग को निर्यातों में हानियां हुई हैं, यह नोट किया जाता है कि लाभ, नकद लाभ और निवेश पर आय से संबंधित सूचना केवल घरेलू प्रचालनों पर ही आधारित है और इसीलिए निर्यातों में संभावित हानियों के कारण प्रभावित नहीं है।

84. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि घरेलू उद्योग ने विगत में हानियों के बावजूद क्षमता विस्तार किया, प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकार्ड में उपलब्ध सूचना यह दर्शाती है कि आवेदक घरेलू उद्योग क्षमता के विस्तार से पहले पूर्व में लाभ में था और यहां तक कि 2017-18 में क्षमता विस्तार के बाद भी घरेलू उद्योग लाभ में था।

85. इस तर्क के संबंध में कि निर्धारित एनआईपी अनुचित रूप से कम है जिसके फलस्वरूप बहुत कम मार्जिन मिलता है और वैश्विक स्तर पर कोई भी देश उस तरीके से कमतर शुल्क नियम का पालन नहीं करता है जिस तरीके से इसे भारत में लागू किया जाता है और इस कारण से, प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करनी चाहिए, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस नियमावली में प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि

वे पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार करते हुए पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करें। यदि निर्धारित क्षति मार्जिन पाटन मार्जिन से कमतर है तब प्राधिकारी से यह अपेक्षित है कि वे शुल्क की सिफारिश करते समय ऐसे क्षति मार्जिन पर विचार करें।

86. इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति गलत तरीके से दर्शाई गई है और अधिक लाभ को वित्तीय विवरण में दर्ज किया गया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी का वित्तीय विवरण केवल उत्पाद के कार्य-निष्पादन को नहीं दर्शाता है और यह घरेलू तथा नियंत दोनों बाजारों में इसके सभी प्रचालनों के लिए कंपनी के कार्य-निष्पादन से संबंधित है। क्षति का विश्लेषण केवल विचाराधीन उत्पाद के लिए और घरेलू बाजार के प्रचालनों के संबंध में किया जाना अपेक्षित है।
 87. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी नियमावली अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 के अनुसरण में विचार किए जाने वाले क्षति संबंधी सभी मानदंड पर किया जाना है, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकारी ने सभी मानदंडों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग से संबंधित सभी मानदंड क्षति को दर्शाएं।
 88. इस दावे के संबंध में कि आवेदक व्यापार उपचारात्मक उपायों का नियमित उपयोग करता है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश जांच करने के बाद ही और इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद ही की गई है कि क्षतिकारक पाटन से वापस होने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना आवश्यक था।
 89. इस अनुरोध के संबंध में कि घरेलू उद्योग को क्षति स्वयं के कारण हुई है और कारणात्मक संबंध मौजूद नहीं है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों के दावे की जांच की है। इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने क्षमता में वृद्धि की है जब मांग में गिरावट आई है, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं की मांग में क्षति की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए आंकड़ों की जांच की है। घरेलू उद्योग की क्षमता में मांग में हुई वृद्धि को देखते हुए बढ़ोत्तरी की गई है।
 90. इस तर्क के संबंध में कि उत्पादन के लागत की गणना न्यूलैंड लेबोरेटरीज लि. और डा. रेडीज लेबोरेट्रीज सहित भारत में कम से कम तीन उत्पादकों के निर्माण की लागत के आधार पर की जा सकती है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि इस सूचना पर घरेलू उद्योग के संबंध में विचार किया जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, चूंकि अन्य घरेलू उत्पादकों से संबंधित सूचना रिकॉर्ड पर नहीं है अतः वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से उस पर विचार नहीं किया जा सकता है।
 91. एनआईपी की गणना में असंगतता के संबंध में यह नोट किया जाता है कि एनआईपी की गणना इस नियमावली के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों के आधार पर की गई है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए उत्पादन से संबंधित सूचना/आंकड़ों जिसे पेशेवर लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित और प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो, को अपनाकर किया गया है।
 92. इस तर्क के संबंध में कि समर्थक उद्योग को असामान्य रूप से अधिक लाभ हो रहा है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि कंपनी का कार्य-निष्पादन जिसे वित्तीय रिपोर्ट में सूचित किया गया है, इसके सभी प्रचालनों के लिए और न कि केवल उत्पाद के लिए कंपनी के कार्य-निष्पादन को दर्शाता है।
- क्ष. क्षति मार्जिन**
93. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की क्षति रहित कीमत घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों और जांच की अवधि के लिए व्यवहारी लागत लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। क्षति रहित कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुँच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। क्षति रहित कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यहीं व्यवहार यूटिलिटियों के साथ भी किया गया। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत में कोई असाधारण अथवा अनावर्ती व्यय नहीं लगाए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूँजी (अर्थात् औसत निवल अचल

परिसंपत्तियां एवं औसत कार्यशील पूँजी) पर उपयुक्त आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) नियमावली के अनुबंध-3 में निर्धारित किए गए अनुसार क्षति रहित कीमत निकालने के लिए कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति थी और उसे अपनाया जा रहा है।

94. संबद्ध देशों से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुँच कीमत निर्धारित की है।
95. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुँच कीमत और क्षति रहित कीमत के आधार पर प्राधिकारी द्वारा उत्पादकों/निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है और वह निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है:

देश	उत्पादक	सामान्य मूल्य/ सीएनवी (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	निर्यात कीमत (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	पाटन मार्जिन (अमेरिकी डॉलर/कि.ग्रा.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (₹)
चीन जन. गण.	शंघाय जिंक्रिसन फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-20
	झेजियांग लघुआ फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-20
	झेजियांग गुओबांग फार्मास्युटिकल कं. लि.	***	***	***	***	0-20
	अन्य	***	***	***	***	0-20

ज्ञ.1 क्षति की जांच

96. संबद्ध उत्पाद के आयातों और घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच यह दर्शाती है कि आयातों की मात्रा पूर्ण दृष्टि से और भारत में उत्पादन तथा मांग के संबंध में बढ़ी है। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों की कटौती कर रहे हैं और कम कीमत पर बिक्री भी सकारात्मक है। संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों से कीमत वृद्धि रुकी है जो अन्यथा उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण हुई होती। घरेलू उद्योग को संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों के कारण कीमत ह्रास हुआ है।
97. यद्यपि, घरेलू उद्योग की क्षमता इस अवधि में बढ़ी है, तथापि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में आधार वर्ष से तुलना करने पर गिरावट आई है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा बढ़ा है, जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग में क्षति की अवधि में उसके लाभ में कमी हुई है और उसे हानियां हो रही हैं। घरेलू उद्योग के नकद लाभ और नियोजित पूँजी पर आय में काफी गिरावट आई है और जांच की अवधि के दौरान यह नकारात्मक हुई है। यह भी नोट किया जाता है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक और काफी है।

ज्ञ.2 गैर-आरोपण विश्लेषण

98. क्षति की मौजूदगी, घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभाव की जांच करने पर प्राधिकारी ने यह जांच की है कि घरेलू उद्योग को क्षति नियमावली में सूचीबद्ध किए गए अनुसार पाटित आयातों को छोड़कर किसी अन्य कारक के कारण हो सकती है।

क. अन्य स्रोतों से आयात

99. चूंकि, चीन जन. गण. का कुल आयातों में 97.76 प्रतिशत हिस्सा है और अन्य देशों से आयात नगण्य है, अतः अन्य देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हो सकती।

ख. मांग में संकुचन

100. यद्यपि, विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में 2017-18 में गिरावट आई, तथापि वह जांच की अवधि में पुनः फिराव हुआ है। इसके अतिरिक्त, घरेलू उद्योग ने वर्तमान मांग में संबद्ध आयातों में बाजार हिस्सा खोया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग को क्षति मांग में किसी संकुचन के कारण नहीं है। किसी भी दशा में क्षति की अवधि के दौरान मांग में कोई संकुचन नहीं है।

ग. खपत के पैटर्न में परिवर्तन

101. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में खपत के पैटर्न में किसी परिवर्तन का कोई साक्ष्य नहीं है। अतः खपत के पैटर्न में परिवर्तन को घरेलू उद्योग को क्षति पहुँचाने वाला कारण नहीं माना जा सकता।

घ. व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाठियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

102. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरीके से प्रतिबंधित नहीं है और उनका देश में स्वतंत्र रूप से आयात किया जा सकता है। यह बताने के लिए किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की शर्तों में कोई परिवर्तन हुआ है।

इ. प्रौद्योगिकी में विकास

103. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सके।

ज. निर्यात निष्पादन

104. ऊपर जांच की गई क्षति संबंधी सूचना का संबंध घरेलू उद्योग के घरेलू बाजार के संदर्भ में उसके निष्पादन से ही है। इस प्रकार, जो क्षति हुई है, वह घरेलू उद्योग के निर्यात निष्पादन के कारण नहीं हो सकती।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध सामानों के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर ही विचार किया है। अतः उत्पादित किए जा रहे/बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभावित कारण नहीं हो सकता।

झ.3 कारणात्मक संबंध की जांच

106. इस प्रकार, यह नोट किया जाता है कि नियमावली के तहत सूचीबद्ध अन्य ज्ञात कारक यह नहीं दर्शाते कि घरेलू उद्योग को इन अन्य कारकों के कारण क्षति हो सकती है। प्राधिकारी ने यह भी जांच की है कि क्या उत्पाद के पाठन से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। निम्नलिखित मानदंड यह दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति पाटित आयातों के कारण हुई है:

- क. संबद्ध सामानों के आयात में पूर्ण दृष्टि से तथा उत्पादन एवं खपत के संबंध में वृद्धि हुई है।
 - ख. संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि घरेलू उद्योग के हिस्से में उसी अवधि में गिरावट आई है।
 - ग. कीमत कटौती सकारात्मक है। संबद्ध देश के संबद्ध सामानों के आयातों का बाजार में उत्पाद की कीमतों पर न्यूनीकरण प्रभाव है।
 - घ. परिणामस्वरूप ग के उत्पादन और बिक्री में इस अवधि में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ,
 - ड. घरेलू उद्योग को वित्तीय हानियां नकद हानियां और निवेश पर नकारात्मक आय हुई है। ,
107. इस जांच की प्रक्रिया के दौरान प्राधिकारी द्वारा इकट्ठे किए गए जांच के आवश्यक तथ्यों और वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में प्राधिकारी द्वारा विश्लेषण किए गए तथ्यों को हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जा रहा है जिससे कि वे इन तथ्यों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकें।

अ. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

108. प्रकटन पश्चात अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त किए गए हैं। प्राधिकारी ने इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन पश्चात अनुरोधों जिसमें वे पुनरावृति शामिल हैं जिनकी पहले ही उपयुक्त रूप से जांच की जा चुकी है और इन अंतिम जांच परिणामों के संगत पैराओं में समुचित रूप से चर्चा की जा चुकी है, की जांच की है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए मुद्दों तथा प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की जांच नीचे की गई है।

अ.१. घरेलू उद्योग के विचार

109. निम्नलिखित प्रकटन पश्चात् अनुरोध घरेलू उद्योग द्वारा किए गए हैं:

- क. इस तर्क में कोई दम नहीं है कि समर्थक उद्योग को असाधारण रूप से अधिक लाभ हो रहा है। वित्तीय रिपोर्ट में सूचित कार्य-निष्पादन कंपनी के सभी कार्य-चालने के लिए और न कि केवल इस उत्पाद के लिए कार्य-निष्पादन का द्वोतक है। इसके अलावा, कंपनी अपनी क्षमताओं का पूर्ण रूप से उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं। वास्तव में, तुलन-पत्र इसे बहुत अधिक हद तक स्पष्ट करेगा कि हमारी कंपनी लगभग 7 प्रतिशत की उद्योग औसत की तुलना में 1.25 प्रतिशत से 2 प्रतिशत के बीच लाभ अर्जित कर रहा है।
- ख. मांग-आपूर्ति में कोई अंतर नहीं है और भारतीय उद्योग पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर उद्योग है। शुल्क लगाए जाने की आवश्यकता के लिए सबसे अधिक दमदार कारण यह है कि भारत आत्मनिर्भर बन गया है। आयात के न होने पर घरेलू उद्योग और अन्य घरेलू उत्पादक देश की कुल मांग को पूरा करने में सक्षम हैं।
- ग. भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए अनुमानित प्रति वर्ष संयुक्त क्षमता भारत में मांग और खपत की तुलना में बहुत अधिक है।
- घ. पाटनरोधी शुल्क लगाना जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। यह अन्य देशों में उत्पादकों द्वारा अनुचित कीमत अंतर जो भारत में इस उद्योग के लिए क्षतिकारक है, का निवारण है। यह संरक्षण नहीं है बल्कि इसके बजाय कीमत में सुधार का एक साधन है। यह आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा और उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। उपभोक्ता के पास अभी भी दो अथवा उससे अधिक आपूर्ति के स्रोत रह सकते हैं।
- ड. वर्तमान में केवल ओफलोसेक्सिन पर पाटनरोधी शुल्क लगता है जो लगभग 50 बल्कि ड्रग्स में से एक है जिसका निर्माण घरेलू उद्योग द्वारा किया जाता है और जो “मेक इन इंडिया” और “आत्म-निर्भर भारत” मिशन में योगदान कर रहा है।
- च. सरकार ने कुछ आवश्यक बल्कि ड्रग्स के लिए आयातों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से “उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना” आरंभ की है। सिप्रोफ्लोसेक्सिन एचसीएल उस सूची में है।
- छ. पाटित आयातों की मौजूदगी में बाजार की कमी के कारण, उत्पादक इस उत्पाद में कार्य करने में सक्षम नहीं हैं। अवसर और उपलब्ध बाजार को देखते हुए घरेलू उत्पादकों के पास न केवल देश में मौजूदा मांग की तुलना में बहुत अधिक क्षमता है और वह उसे पूरा करते हैं बल्कि वे मांग में किसी पूर्वाभासी वृद्धि को पूरा करने तथा अतिरिक्त उत्पादन से निर्यात कर देश के लिए बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सक्षम होंगे और उसके द्वारा वास्तव में जहां तक इस उत्पाद का प्रश्न है, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को पूरा किया जा सकेगा।
- ज. प्राधिकारी को ऐसे उत्पादों के लिए चीन के उत्पादकों की दया पर इस देश को नहीं छोड़ना चाहिए। प्राधिकारी इस पर विचार करने के लिए हकदार हैं कि क्या यह एक सही मामला है जहां सरकार क्षति के मार्जिन की उपेक्षा कर सकती है और पाटन मार्जिन की पूरी सीमा तक पाटनरोधी शुल्क लगा सकती है। यह देखते हुए कि यह उत्पाद फार्मा एफीआई है, और इसका संबंध देश के स्वास्थ्य क्षेत्र से है, उपभोक्ताओं पर प्रस्तावित शुल्क के किसी वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव, अर्थक्षम और गतिशील उद्योग की मौजूदगी इस देश के लिए अपेक्षाकृत बड़ी चिंता होनी चाहिए।

- झ. इस उत्पाद का मुख्य रूप से उत्पादन चीन और भारत में किया जाता है और इस प्रकार घरेलू उत्पादन वर्तमान उत्पाद में अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के हेल्थ केयर के लिए इस उत्पाद की संगतता और महत्व पर विचार करते हुए, यदि भारत सरकार ऐसे आवश्यक दबावों के लिए इस देश को चीन के हाथ में छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं है तब देश को घरेलू निर्माण की आवश्यकता है। इस उत्पाद का घरेलू उत्पादन नहीं होने का आशय यह होगा कि हम चीन पर पूर्ण रूप से निर्भर रहें।
- ज. प्राधिकारी ने पूर्व में पेनिसिलीन-जी पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की लेकिन तथापि सरकार ने इन सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया। व्यापार के गैर-अर्थक्षम होने के साथ चीन से पिछले एक दशक में निम्नलिखित सस्ते आयातों के बाद इस उत्पाद की कीमतें अचानक बहुत तेजी से गिरी और मेक्स-जीबी, एचएएल, जेके फार्मा और टीजीबीएल जैसे भारतीय निर्माताओं ने उत्पादन बंद कर दिया। एलेम्बिक ने भी पेन-जी सुविधा बंद कर दी थी लेकिन इसने बाद में फिर से शुरू कर दिया। पेनिसिलीन-जी की दशा के विपरीत, मेट्रोनिडाजोल और डिक्लोफेनेक सोडियम के मामले में, सरकार द्वारा दी गई सहायता के फलस्वरूप देश में अब एक अर्थक्षम और गतिशील घरेलू उद्योग है। देश अब आयातों पर निर्भर नहीं है और यदि आवश्यकता पड़ी तो घरेलू उत्पादक के पास भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है। प्राधिकारी को महामारी के वर्तमान समय में इन दबाओं के महत्व पर विचार करने तथा राष्ट्र को आत्म-निर्भर बनाने पर विचार करने की जरूरत है।
- ट. उपभोक्ताओं से विरोध न होना यह दर्शाता है कि उपभोक्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं हुए हैं।
- ठ. व्यापार उपचारात्मक शुल्क पाटन जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जैसी अनुचित कार्य-पद्धतियों को समाप्त करने के लिए लागू किया जाता है। शुल्क लगाना क्षतिग्रस्त घरेलू उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते समय भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित करने के लिए है।

अ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

110. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन पश्चात् निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- क. निर्यातकों ने उनके द्वारा दिए गए सभी उत्तरों में तथा किए गए सभी अनुरोधों में दिनांक 7 सितंबर, 2018 की व्यापार सूचना सं. 10/2018 के अनुबंध-II का विधिवत् अनुपालन किया है।
- ख. यह कानून पाटन के पूर्ण मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश करने में प्राधिकारी को कोई विवेकाधिकार नहीं देता है। इस कारण से, प्राधिकारी के लिए संबद्ध जांच में उच्चतर मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश करना विधिक नहीं है।
- ग. क्षति रहित कीमत की गणना करने के लिए कानून पर पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में भी विचार किया गया है और उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। भारत की पाटनरोधी व्यवस्था 1995 से मौजूद है और इसमें अनेक जांचों में आरती ड्रग्स लि. सहित विभिन्न उत्पादों के विभिन्न घरेलू उद्योगों को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया है।
- घ. वर्ष 2015 में, सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो पीयूसी का एक घरेलू उत्पादक है ने राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सिप्रोफ्लोसाक्सिन 250 मि.ग्रा. की उच्चतम कीमत निर्धारित कर, जारी की गई दिनांक 13.07.2015 की अधिसूचना एस.ओ. सं. 1882(ई) के विरुद्ध याचिका दायर की। कंपनी द्वारा उठाए गए मुद्दे अनुसूचित निर्माण की उच्चतम कीमत की गणना करने के लिए सही पद्धति के संबंध में था। वैसा ही मामला 2018 में भी सामने आया जब सन फार्मास्युटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 250 मि.ग्रा. सिप्रोफ्लोसाक्सिन और 500 मि.ग्रा. सिप्रोफ्लोसाक्सिन टेबलेट की उच्चतम कीमत का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत प्राधिकारी द्वारा जारी की गई दिनांक 28.07.2017 की अधिसूचना एस.ओ. सं. 2401(ई) के विरुद्ध दो याचिकाएं दायर की।
- ड. प्रारंभिक पाटनरोधी शुल्क को अनापेक्षित रूप से लगाने के संबंध में, प्राधिकारी ने इस याचिका में सभी मानदंडों का मूल्यांकन किए बिना शीघ्रता से अंतरिम शुल्क की सिफारिश की है और दिनांक 15 जून, 2020 की अधिसूचना सं. 6/36-2019-डीजीटीआर के संदर्भ में प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किया।

- च. प्राधिकारी ने सही तरीके से इसका मूल्यांकन नहीं किया है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ब) और पाटनरोधी शुल्क संबंधी करार के अनुच्छेद 4.1 के अनुसरण में “उस वस्तु के घरेलू उत्पादन का बड़ा अनुपात” है। प्रतिवादियों ने इसी-फास्टनर्स(चीन) में अपीलीय निकाय के निर्णय पर विचार किया है।
- छ. घरेलू उद्योग 2020 के आरंभ से अपने उत्पादों की विभिन्न दायरे पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध करने की निरंतर कार्य-पद्धति को अपनाता रहा है और उसे अभी भी क्षति हो रही है। संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक ने जिसने इस जांच में भाग लिया है, को कोई भी क्षति नहीं होती रही है और वह अच्छा करता आ रहा है। इस संबंध में, चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से पोलिस्टर स्टेबल फाइबर की डीजीटीआर जांच पर विश्वास किया गया है और चीन जन.गण., पोलैंड, रूस और रोमानिया से बाल बियरिंग्स (50 मी.मी. बोर के दाय तक) की जांच पर विश्वास किया है।
- ज. प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण शेनियांग मातसुशिता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. और अन्य, (2005) 3 एससीसी 39 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध है। भौगोलिक रूप से, वैश्विक सिप्रोफ्लोसाक्सिन का उत्पादन सात प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् नार्थ अमेरिका, लेटिन अमेरिका, यूरोप, ईस्ट एशिया, दक्षिण एशिया, ओसियानिया और मध्य पूर्व एवं अफ्रीका में अलग-अलग किया जाता है। नार्थ अमेरिका समग्र वैश्विक सिप्रोफ्लोसाक्सिन बाजार में हावी है। वैश्विक सिप्रोफ्लोसाक्सिन बाजार में प्रतिस्पर्धा करने वाले कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण कंपनियां नोवार्टिस इंटरनेशनल एजी, एलर्जन पीएलसी, मर्क एंड कं. इंक, सिपला लिमिटेड, बेयर एजी, काडिला हेल्थकेयर, जेनमार्क फार्मास्युटिकल्स, हेक्सल, सैनोफिसिनथिलाबो, फाइजर, और माइलन लैबोरेट्रीज लि. अन्य में से हैं। इस कारण से यह निष्कर्ष कि सिप्रोफ्लोसाक्सिन का उत्पादन मुख्य रूप से भारत में किया जाता है और चीन जन.गण. का इसमें कोई तथ्य नहीं है और भारत में उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की संरचना में कोई दम नहीं है।
- झ. घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत चीन जन.गण. से कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बहुत अधिक है।
- ञ. घरेलू उद्योग लगातार कर्मचारियों की नियुक्ति कर रहा है और क्षति के विश्लेषण की अवधि से जांच की अवधि तक मजदूरी में वृद्धि हुई है।
- ट. घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2015-16 की तुलना में 54 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और इसमें वर्ष 2015-16 से प्रत्येक वर्ष 10 प्रतिशत से अधिक की वर्ष-दर-वर्ष निरंतर वृद्धि दर्ज की है।
- ठ. घरेलू उद्योग स्वयं यह दावा कर रहा है कि इसने सबसे अधिक राजस्व और कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) प्राप्त किया है। घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में वृद्धि स्वतंत्र आधार पर वर्ष 2017-2018 से तुलना किए जाने पर 27.51 प्रतिशत है।
- ड. गोदावरी ड्रग्स लिमि. जो सिप्रोफ्लोसाक्सिन का घरेलू उत्पादक है, ने यह उल्लेख किया कि कंपनी के कुल कारोबार का 91 प्रतिशत स्वयं सिप्रोफ्लोसाक्सिन से होता है (वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण की सं. 17) और कंपनी जांच की अवधि के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक लाभ अर्जित कर रहा है अर्थात् वे असाधारण रूप में अच्छा कर रहे हैं।
- ढ. दि गोदावरी ड्रग्स लि. को सकारात्मक कर-पश्चात लाभ/ईपीएस प्रति शेयर आय होने की बजाय कोई हानि नहीं होती रही है जैसाकि पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान ऊपर में दिया गया है।

अ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

111. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध पुनरावृत्ति की प्रकृति के हैं। इन अनुरोधों की जांच पहले ही इस जांच परिणाम में उपयुक्त स्थानों पर की गई है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अतिरिक्त/नए संगत अनुरोधों की जांच नीचे दिए गए अनुसार की है:
- क. हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावे जिसका उल्लेख ऊपर में किया गया है, के संबंधे में प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावे पर विचार किया है और संतुष्ट होने पर उसकी अनुमति दी।

- ख. सिप्रोफ्लोसाक्सिन 250 मि.ग्रा. और सिप्रोफ्लोसाक्सिन 500 मि.ग्रा. टेबलेट की उच्चतम कीमत का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कीमत निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिनांक 28.07.2017 की अधिसूचना एस.ओ.सं. 2401(ई) के विश्वद्वय याचिकाएं दायर करने के संबंध में तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि ड्रग्स (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 (“ईपीआई”) के अंतर्गत लगाई गई कीमत उच्चतम सीमा निर्माण के लिए है और न कि एपीआई अथवा बल्कि ड्रग्स के संबंध में है जबकि वर्तमान जांच अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले एपीआई के लिए है जबकि सीप्रोफ्लोसाक्सिन निर्माण सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 30 के अंतर्गत आता है।
- ग. अनेक हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग को क्षति होने का खंडन किया है। हितबद्ध पक्षकारों ने कुछ क्षति संबंधी मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में सुधार का उल्लेख किया है। हालांकि, यह एक सुस्थापित कानूनी स्थिति है कि यह आवश्यक नहीं है कि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन क्षति संबंधी प्रत्येक मानदंड के मामले में अपकर्ष दर्शाना चाहिए और कुछ मानदंडों में सुधार का आशय क्षतिकार नहीं होना नहीं है। इस कारण से, यह माना गया है कि जहां तक घरेलू उद्योग का कार्य-निष्पादन कुछ मानदंडों के मामले में अपकर्ष को दर्शाते हैं, ऐसा अपकर्ष अन्य मानदंडों में सकारात्मक घटनाक्रम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।
- घ. इस तर्क के संबंध में कि संबद्ध वस्तुओं के अन्य उत्पादक जिन्होंने इस जांच में भाग नहीं लिया है, को कोई क्षति नहीं होती रही है और वे अच्छा करते रहे हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य घरेलू उत्पादकों से संबंधित सूचना रिकॉर्ड पर नहीं है और हितबद्ध पक्षकारों ने अपने तर्क के समर्थन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह निष्कर्ष निकालना उपयुक्त नहीं होगा कि वर्तमान निर्धारण के उद्देश्य से अन्य उत्पादकों को हुई क्षति के होने अथवा अन्यथा के संबंध में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला जा सकता है।
- ड. सिप्रोफ्लोसाक्सिन का वैश्विक स्तर पर उत्पादन और सामान्य मूल्य की संरचना के संबंध में तर्क के बारे में यह नोट किया जाता है कि विचाराधीन उत्पाद सिप्रोफ्लोसाक्सिन एचसीएल एपीआई है जो अध्याय 29 के अंतर्गत आता है जिसका मुख्य रूप से उत्पादन भारत और चीन में किया जा रहा है। हितबद्ध पक्षकारों ने सीमा प्रशुल्क अधिनियम के अध्याय 30 के अंतर्गत आने वाले सिप्रोफ्लोसाक्सिन निर्माण का हवाला दिया है जो वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से परे है।
- च. चीन जन.गण. से कड़ी सामग्री अनुपलब्धता के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन की क्षिति उच्च लागत के संबंध में इस तर्क के बारे में, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा वहन की गई वास्तविक लागत पर विचार किया है और रिकॉर्ड में इसकी सूचना दी है। घरेलू उद्योग द्वारा सूचित किए गए उत्पादन की लागत का सत्यापन प्राधिकारी द्वारा किया गया है।
- छ. समर्थक कंपनी द्वारा अर्जित क्षिति लाभ के बारे में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच परिणाम घरेलू उद्योग की सूचना के आधार पर है।
- ज. पोलिस्टर स्टेपल फाइबल बाल बियरिंग्स के संबंध में विगत जांचों का संदर्भ लिए जाने के बारे में, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि निर्धारण भी विशिष्ट मामले के तथ्यों के आधार पर है। यह उपयुक्त नहीं होगा कि वर्तमान मामले से इसकी तुलनीयता स्थापित किए बिना किसी विगत निर्धारण का संदर्भ लिया जाए।
- झ. जहां तक शेनयांग मितसुशिता एस. बैटरी कं. लि. बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लि. में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का प्रश्न है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की लागत अथवा कीमत या भारत सहित अन्य देशों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले ऐसे तीसरे देश से कीमत के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है।
- ज. जहां तक मजदूरी और कर्मचारियों में क्षिति वृद्धि का प्रश्न है, यह नोट किया जाता है कि इन आधारों पर लागतों में कोई असामान्य वृद्धि नहीं हुई है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

112. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य तौर पर पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य घरेलू उद्योग को पाटन की अनुचित व्यापार कार्य-पद्धतियों के द्वारा हुई क्षति को समाप्त करना है जिससे भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके जो देश के सामान्य हित में है। हितबद्ध पक्षकारों ने यह सिद्ध किया है कि शुल्कों को लगाए जाने से जनजित पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने जा रहा है।
113. यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध वस्तुओं का उपयोग करते हुए निर्मित उत्पाद की कीमत के स्तरों पर प्रभाव पड़ सकता है और परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में पाटनरोधी शुल्क से विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की लेवी घरेलू उद्योग को क्षति का निवारण करने के लिए आवश्यक सीमा तक सीमित हो, कभी नहीं आएगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी शुल्क लगाने से पाटन की कार्य-पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होगा, घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन में गिरावट रुक जाएगी और संबद्ध वस्तुओं के उपभोक्ताओं को अपेक्षाकृत व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

ण. निष्कर्ष

114. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने पर और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:
- क. विचाराधीन उत्पाद का निर्यात संबद्ध देशों से भारत को उसके सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है।
 - ख. घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
 - ग. वास्तविक क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से हुई है।

त. सिफारिशें

115. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रयाप्त अवसर दिया गया था ताकि वे पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलू पर सकारात्मक सूचना उपलब्ध करा सकें। इस नियमावली के तहत विनिर्दिष्ट प्रावधानों के संदर्भ में पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और उसे पूरा किए जाने पर, प्राधिकारी का यह विचार है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना पाटन और क्षति को निष्प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। इस कारण से प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं।
116. इस नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1) (ख) में निहित प्रावधान के संदर्भ में, प्राधिकारी पाटन का मार्जिन और क्षति का मार्जिन में से कमतर के बराबर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त की जा सके। इसलिए, प्राधिकरण इसे आवश्यक मानता है और केंद्रीय देशों के विदेश मंत्रालय द्वारा अनंतिम शुल्क लगाने की अधिसूचना जारी करने की तिथि से यहां वर्णित रूप और तरीके में विषय के देशों से विषय वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है। अधिसूचना संख्या 28/2020-ग्राहक (ADD) दिनांक 2 सितंबर, 2020 तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क चीन जन.गण., इंडोनेशिया और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए शुल्क तालिका के कॉलम 3 में उल्लिखित वस्तुओं के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तिथि से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र.स.	प्रशुल्क शीर्ष*	वस्तुओं का विवरण	मूल देश अथवा निर्यातक देश	निर्यातक देश	उत्पादक	शुल्क राशि	मुद्रा	यूनिट
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	शंघाय जिक्सिन फार्मास्युटिकल कं. लि..	2.38	अमेरिकी डॉलर	कि. ग्रा.
2	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ज़ेजियांग लंधुआ फार्मास्युटिकल कं. लि.	0.91	अमेरिकी डॉलर	कि.ग्रा.
3	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ज़ेजियांग गुओवांग फार्मास्युटिकल कं. लि.	1.87	अमेरिकी डॉलर	कि.ग्रा.
4	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	क्रम सं. 1, 2 और 3 पर दिए गए उत्पादकों को छोड़कर कोई भी उत्पादक	3.27	अमेरिकी डॉलर	कि.ग्रा.
5	29419030	सिप्रोफ्लोक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड	चीन जन. गण. को छोड़कर कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	3.27	अमेरिकी डॉलर	कि.ग्रा.

* सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सूचक है।

117. उपर्युक्त विषय, 15 जून, 2020 को अधिसूचित प्रारंभिक निष्कर्षों की पुष्टि की जाती है।

आगे की प्रक्रिया

118. केन्द्र सरकार द्वारा इन जांच परिणामों को स्वीकार किए जाने के बाद इनके विरुद्ध अपील सीमा प्रशुल्क अधिनमय 1975 के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

बी. बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 7th January, 2021

Case No. ADD-OI-32/2019

Subject : Anti-dumping investigation concerning imports of “Ciprofloxacin Hydrochloride” originating in or exported from China PR.

F. No. 6/36/2019-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act), and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter also referred to as “the Rules” or “the AD Rules”) thereof:

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application through TPM Consultants, from M/s Aarti Drugs Ltd. (hereinafter also referred to as "the Applicant" or "petitioners")) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as "the Rules") for imposition of anti-dumping duty on imports of "Ciprofloxacin Hydrochloride" or "Ciprofloxacin HCL" (hereinafter also referred to as "the product under consideration" or "PUC" or "subject goods") from People's Republic of China (hereinafter also referred to as the "subject country"). M/s Godavari Drugs Limited, another domestic producer of the subject goods, supported the application filed by the Applicant.
2. The Authority, on the basis of sufficient prima-facie evidence submitted by the Applicant, issued a public notice vide Notification No. 6/36/2019- DGTR dated 10th January 2020, published in the Gazette of India, initiating the subject investigation in accordance with Rule 5 of the Rules to determine existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods, originating in or exported from the China PR, and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the Domestic Industry.
3. The Authority having regard to the Act and the Rules, considered it appropriate to recommend interim duties and issued preliminary finding vide Notification No. 6/36/2019- DGTR dated 15th June 2020, recommending imposition of provisional anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from China PR. Accordingly, the Central Government vide Notification No.28/2020-Customs(ADD) dated 2nd September 2020 imposed provisional anti-dumping duties on imports of the subject goods, originating in or exported from the China PR which are valid for 6 months.

B. PROCEDURE

4. The procedure described herein below has been followed by the Authority with regard to the subject investigation:
 - a. The Authority notified the Embassy of the Subject Country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
 - b. The Authority issued a public notice dated 10th January 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from subject country.
 - c. The Embassy of subject country in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Rules. The Authority sent a copy of the initiation notification to the Government of the subject country, through its Embassy in India, known producers/exporters from the subject country, known importers/users and the domestic industry as well as other domestic producers as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within the prescribed time limit.
 - d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its Embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra. A copy of the non-confidential version of the application was also made available in the public file and provided to other interested parties, wherever requested.
 - e. The Authority also forwarded copy of the notice to known producers/ exporters from the subject country, known importers/users in India, other Indian producers and the domestic industry as per the addresses made available by the Applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification. The Authority sent Exporter's Questionnaire to the following known producers/exporters to elicit relevant information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
 - i. M/s Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co. Ltd
 - ii. M/s Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Imp
 - iii. M/s Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co Ltd.

- f. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from China PR to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- g. In response to the initiation of the subject investigation, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response:
- i. M/s Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co Ltd
 - ii. M/s Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co Ltd
 - iii. M/s Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Import & Export Co Ltd
 - iv. M/s Shangyu Jingxin Pharmaceuticals Co Ltd
- h. The Authority sent Importer's Questionnaire to the following known importers/users of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rules:
- i. M/s Pharma Zone
 - ii. M/s Shalina Laboratories Pvt Ltd
 - iii. M/s Minerva Biogenix Pvt. Ltd.
 - iv. M/s Pinnacle Life Science Private Limited
 - v. M/s Laborate Pharmaceutical India Limited
 - vi. M/s Sneha Medicare Pvt Ltd
 - vii. M/s Africure Pharmaceuticals (India) Private Limited
 - viii. M/s Del Trade International Private Limited
 - ix. M/s Sevantilal & Sons
 - x. M/s Bal Pharma Limited
 - xi. M/s Pratistha Pharma
 - xii. M/s Granules India Limited
 - xiii. M/s C J Shah And Co
 - xiv. M/s Medico Remedies Limited
 - xv. M/s Aurobindo Pharma Limited
 - xvi. M/s Cadila Pharmaceuticals Ltd.
 - xvii. M/s Flamingo Pharmaceuticals Ltd.,
 - xviii. M/s Prashi Pharma Private Limited
 - xix. M/s Syncom Formulations (India)Limited.
 - xx. M/s Micro Labs Ltd
 - xxi. M/s Mancare Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
 - xxii. M/s Gorang International
 - xxiii. M/s Granules India Limited
 - xxiv. M/s Brawn Laboratories Ltd
 - xxv. M/s Theon Pharmaceuticals Ltd.
 - xxvi. M/s Agog Pharma Ltd.
 - xxvii. M/s Aquatic Remedies Limited
 - xxviii. M/s Medopharm
 - xxix. M/s Umedica Laboratories Pvt. Ltd.

- i. None of the importers/users except M/s Micro labs Limited has responded and filed importer's questionnaire response.
- j. The Authority sent notice of initiation to the following other domestic producers, intimating them of the initiation of investigation with a request to provide relevant information to the Authority in the form and manner prescribed:
 - i. M/s Aurobindo Pharma Limited
 - ii. M/s Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
 - iii. M/s Neuland Laboratories Limited
 - iv. M/s Emmennar Pharma Private Limited
 - v. M/s Sreepathi Pharmaceuticals Limited
 - vi. M/s Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- k. None of the other domestic producers have responded or participated in the present investigation.
- l. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/submissions made by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties. Submissions made by all the interested parties to the extent considered relevant at this stage have been taken into account in these final findings.
- m. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- n. The Non-injurious Price (NIP) based on the optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the Rules has been worked out so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- o. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the physical inspection through on-spot verification of the information was not carried out by the Authority. Desk Verification of the information provided by the applicant/producers/ exporters, to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary rectification, to the extent deemed necessary, has been relied upon for the purpose of these final findings.
- p. Other submissions made by the interested parties during the course of this investigation, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered by the Authority, in these final findings.
- q. The Period of Investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from April 2018 – June 2019 (15 months). The examination of trends in the context of injury analysis covered the periods April 2015- March 2016, April 2016-March 2017, April 2017-March 2018 and the POI.
- r. Due to the worldwide outbreak of COVID-19 and consequent restrictions imposed by different countries, including India, the Authority in accordance with Rule 6(6) of the AD Rules and Trade Notice No. 01/2020 dated 10th April 2020, conducted oral hearings through video conferencing on 19th October 2020 to provide an opportunity to the interested parties to present relevant information orally before the then Designated Authority in office.
- s. All the parties who had attended the above mentioned oral hearings were advised to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinders, if any. The arguments made in such written submissions and rejoinders received from the interested parties have been considered, to the extent deemed necessary, for the purpose of these final findings.
- t. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation, including in response to the Preliminary Findings, wherever found relevant, have been addressed by the Authority, in these Final findings.

- u. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- v. The Authority has considered the arguments raised and information provided by all the interested parties till this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- w. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the final findings on the basis of the facts available.
- x. ‘***’ in these final findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- y. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority as US\$1 = 70.73

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as:

“The product under consideration is “Ciprofloxacin Hydrochloride” or “Ciprofloxacin HCL”.

Ciprofloxacin Hydrochloride is used to treat different types of bacterial infections, including skin infections, bone and joint infections, respiratory or sinus infections, urinary tract infections, and certain types of diarrhoea. It acts as anti-infective agent, a topoisomerase IV inhibitor, an antibacterial drug, an EC 5.99.1.3 [DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)] inhibitor, a DNA synthesis inhibitor, an antimicrobial agent, an environmental contaminant and a xenobiotic.

The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act in the name of ‘Ciprofloxacin HCL and its salts’ (subheading 29419030). The Custom classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.”

C.1 Views of the domestic industry

6. The following are the submissions made by domestic industry with regard to product under consideration and like article:
- a. The product under consideration (PUC) is Ciprofloxacin HCL, a quinolone that is quinolin-4(1H)-one bearing cyclopropyl, carboxylic acid, fluoro and piperazin-1-yl substituents at positions 1, 3, 6 and 7, respectively.
 - b. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is weight in Kg/ MT
 - c. Ciprofloxacin HCL is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act in the name of ‘Ciprofloxacin HCL and its salts’. The dedicated code for Ciprofloxacin and its salts is 29419030. However, the customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigations.
 - d. The goods produced by the Applicant are like article to the imported goods as they are comparable in terms of chemical & technical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods, and are technically and commercially substitutable.
 - e. There is no known significant difference in the technology employed by the domestic industry and the producers in subject country.

C.2 Views of the other interested parties

7. None of the other interested parties has made any submission with regard to PUC.

C.3 Examination by the Authority

8. The product under consideration, as defined in the notice of initiation, is “Ciprofloxacin Hydrochloride” or “Ciprofloxacin HCL”. Ciprofloxacin Hydrochloride is used to treat different types of bacterial

infections, including skin infections, bone and joint infections, respiratory or sinus infections, urinary tract infections, and certain types of diarrhoea. It acts as anti-infective agent, a topoisomerase IV inhibitor, an antibacterial drug, an EC 5.99.1.3 [DNA topoisomerase (ATP-hydrolysing)] inhibitor, a DNA synthesis inhibitor, an antimicrobial agent, an environmental contaminant and a xenobiotic.

9. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under the tariff code 29419030, in the name of ‘Ciprofloxacin HCL and its salts’. The Customs classification is indicative only and not binding on the scope of the investigation.
10. None of the interested parties have made any submissions for modification of the scope of product under consideration post initiation of investigation. Accordingly, the Authority has considered the product under consideration, as defined in the notice of initiation, for the purpose of the present final findings.
11. The Applicant claimed that the Ciprofloxacin HCL produced by it and that imported from the subject country are produced using the same basic raw materials having broadly similar manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification. The contention of the Applicant has not been disputed by the other interested parties. The Authority holds that the product produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from subject country in terms of Rule 2(d) of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Views of the domestic industry

12. Following are the submissions made by the Applicant with regard to scope of the domestic industry and standing:
 - a. The application has been filed by M/s Aarti Drugs Ltd. and supported by M/s Godavari Drugs Limited, another producer of the product under consideration.
 - b. There are six more known domestic producers of the product under consideration, namely,
 - i. M/s Aurobindo Pharma Limited,
 - ii. M/s Dr. Reddy's Laboratories Ltd.,
 - iii. M/s Neuland Laboratories Limited,
 - iv. M/s Emmennar Pharma Private Limited,
 - v. M/s Sreepathi Pharmaceuticals Limited and
 - vi. M/s Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
 - c. The Applicant is neither related to an importer in India nor an exporter from the subject country, and has not imported the product under consideration from the subject country.
 - d. The Applicant holds a major proportion of total domestic production of the subject goods in India and thus, constitutes domestic industry.
 - e. The applicant has assessed the production of the other producers based on market intelligence as there is no published information available. The Authority sent a communication to other domestic producers advising them to file information in the form and manner prescribed concerning injury determination. However, none of the other domestic producers have filed complete injury information. The evidence submitted on the record and verified by the Authority, shows that the Applicant commands a major proportion and the applicant, along with the supporter, accounts for more than 50% of the total production of the subject goods in India. None of the other producers have disputed the above facts.
 - f. The applicant was never against calling information from other domestic producers to assess the total Indian production and the standing of the domestic industry. However, if other domestic producers have not cooperated with the Authority, the domestic industry cannot be penalised for the same.
 - g. The Authority has recorded the preliminary findings on the basis of information of applicant and since injury to the domestic industry is not based on data of the supporting domestic producer, the possibility that such domestic producer may not have provided information as per format does not vitiate the determination.

D.2. Views of the other interested parties

13. Following are the submissions made by the other interested parties with regard to scope of the domestic industry and standing:

a. No proof or any evidence is given to support the actual percentage of production of all other producers, and that Neuland's Laboratories Limited and M/s Dr. Reddy's Laboratories Ltd have only produced to export. As per the Annual Report, these two producers sell more than 30% of their production in the Domestic Market.

D.3 Examination by the Authority

14. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as under:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof; in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers".

15. The application has been filed by M/s Aarti Drugs Ltd. The Applicant is not related to any importer or exporter of subject goods in the subject country, nor have they imported subject goods from subject country. The Applicant is the largest producer of the subject goods in the country. Further, the application filed by the Applicant was supported by M/s Godavari Drugs Ltd., another domestic producer of the subject goods. Apart from the Applicant and supporter, following are the other Indian producers of the subject goods in India:

- i. M/s. Aurobindo Pharma Limited
- ii. M/s Dr. Reddy's Laboratories Ltd.
- iii. M/s Neuland Laboratories Limited
- iv. M/s Emmennar Pharma Private Limited
- v. M/s Sreepathi Pharmaceuticals Limited
- vi. M/s. Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

16. At the stage of initiation and thereafter, the Authority sent a communication to other domestic producers advising them to file information in the form and manner prescribed with regard to injury determination. However, none of other domestic producers have filed complete injury information in the prescribed format.

17. As regards the submission that no evidence has been provided to support the actual production of non-petitioning other producers, the Authority notes that none of the interested parties have provided evidence contrary to evidence presented by the applicant. Some interested parties relied upon the annual report of Neuland's Laboratories Limited and M/s Dr. Reddy's Laboratories Ltd and contended that these companies sell more than 30% of their production in the Domestic Market. It is however noted the annual report of these companies show segment analysis of the company's turnover and is not specific to the product under consideration.

18. The evidence on record shows that the Applicant commands a major proportion (43%) in the total domestic production in India. Further, the Applicant, along with the supporter, account for more than 50% of the total production of the subject goods in India. Accordingly, the Authority holds that the Applicant constitutes domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and considers that the application satisfied the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Views of the domestic industry

19. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality:

- a. Applicant has disclosed all the essential information in the non-confidential version of the application in accordance with Rule 7 of the Rules and as per Trade Notice No. 10/2018 dated 7th September 2018.
- b. Indexed information has been provided wherever possible. The injury analysis is essentially an

- analysis of trend which can be easily seen through trends of various parameters provided in the application.
- c. The non-confidential version of the response filed by the other interested parties is grossly deficient and should be rejected.
 - d. Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co Ltd has claimed excessive confidentiality with regard to shareholding structure, production process, full value chain, and production facilities. It has failed to disclose details of its related parties and procurement of raw materials.
 - e. Zhejiang Langhua has claimed product list and corporate structure as confidential, even though the same is available in public domain.
 - f. Shengyu Jingxin Pharmaceutical Co Ltd has claimed excessive confidentiality with regard to the working of the company itself, the holding company and its activity, and other related companies engaged in production of the subject goods. Further, it has not provided details of its shareholding structure, channel of distribution, product list, raw material procurement, product description and production process.
 - g. Zhejiang Jingxin Pharmaceuticals Export and Import Co Ltd (Trader) has claimed excessive confidentiality with regard to its shareholding structure, sales flow chart, and its related company(ies) engaged in the production of the subject goods.
 - h. Supporting producers have neither provided relevant information to the applicant nor the applicant has authority to force them as they have not authorized the applicant to disclose even indexed data. Indexed data also carries significant information.
 - i. NIP is a highly business-sensitive information and cannot be disclosed on an actual basis or even in a range. The Authority also does not disclose NIP or normal value or export price even in a range. The interested party is assuming that the Authority proceeds blindfold.
 - j. The applicant has already submitted the non-confidential version of DGCI&S Transaction wise import data vide letter dated 7th February 2020.
 - k. The NCV application mentions that balance sheets of the applicant can be seen on the companies' website. Quality Policy, Sales Policy, of the applicant is highly business-sensitive information, disclosure of which would be of significant competitive advantage to the competitors.

E.2. Views of the other interested parties

20. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality:
- a. The standard provided for the disclosure of the ‘Non-Injurious Price’ in Trade Notice 10/2018 dated 7th September, 2018 is ‘Aggregated actual data must be provided in actual figure range +/- 10%’. The same has not been complied with by the domestic industry and the domestic industry has also not shown any good cause for such confidentiality. It seems that the NIP may have been deliberately concealed since the import price of the subject imports is higher than the non-injurious price.
 - b. Godavari Drugs Limited is a supporting domestic producer in the subject investigation. Trade Notice No. 13/2018 dated 27th September 2018 states the information required to be provided by supporting domestic producers and the prescribed formats for the same. Trade Notice 14/2018 dated 1st October 2018 provides guidelines for disclosure of such information in confidential and non-confidential version. The requirements of neither of the trade notices have been complied with. The supporting domestic producer has provided no relevant information to the Respondent.
 - c. The Petitioner has violated the provisions of confidentiality as per Rule 6 and & of the AD Agreement and Trade notices 10 of 2018, 13 of 2018 and 14 of 2018.
 - d. The Petitioner has not provided Transaction wise import data in excel format to the Respondent as per the recent ruling of Hon’ble CESTAT in Exotic Decor Pvt Ltd. Versus Designated Authority dated 12th June 2020.
 - e. The Annual reports, Quality Policy, Sales Policy, of the Petitioner and the supporting Industry as confidential. The Authority has violated Article 6.5 of the AD Agreement. Reliance placed on Panel Report in EC – Fasteners (China)

- f. The Respondent has the right to know the calculation done by the Authority for determining the NIP and injury margin as it will have an impact on the margin of the Exporters and requests to provide a non-confidential summary of the same.

E.3 Examination by the Authority

21. Various submissions made by the Applicant as well as other interested parties during the course of the investigation with regard to confidentiality, to the extent considered relevant by the Authority, have been examined and addressed as follows.
22. The Authority made available non-confidential version of the information provided by various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection as per Rule 6(7).
23. As regards information from supporting producers, the Authority has recorded present findings on the basis of information of Applicant domestic industry and has not taken into account the support to the petition. Since injury to the domestic industry is not based on data of the supporting domestic producer, the possibility that such domestic producer may not have provided all information strictly as per format does not vitiate the present determination and right of the Applicant domestic industry. The Authority has prescribed a format for supporting companies only with a view to analyse the performance of such supporting domestic producers. In a situation where supporting domestic producers have not provided information in the prescribed formats, the Authority has not examined possible injury to such other domestic producers. However, the right of Applicant with respect to “standing” within the meaning of Rule 5(3) cannot be diluted even if the supporting domestic producers merely support the petition without providing any information whatsoever.
24. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule(2) of rule 12, sub-rule(4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

25. As regards the contentions with regard to confidentiality of information, it is noted that information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidence submitted by various interested parties in the form of public file. The information related to imports, performance parameters and injury parameters of domestic industry has been made available in the public file. Business sensitive information has been kept confidential as per practice.
26. As regards the contention that excel file of transaction-by-transaction imports were claimed confidential by the domestic industry, the procedure for sharing and procuring import data has been laid down in the Trade Notice 07/2018 dated 15th March 2018. It provides that (i) the sorted import data relied upon by the domestic industry can be shared in hard copy & (ii) interested parties can seek authorization from the Authority for seeking raw transaction by transaction import data from DGCI&S. Hard copy of the sorted import data was made accessible to the interested parties based upon declaration/undertaking as per prescribed format. The interested parties who requested for procurement of import data from DGCI&S

and provided undertaking as per Trade Notice 07/2018 were also granted authorization to obtain import data in excel file from DGCI&S. The Authority thus notes that the procedure now being applied is consistent, uniform across parties and investigations and provides adequate opportunity to the interested parties to defend their interests.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Views of the domestic industry

27. Following are the submissions made by the Applicant with regard to scope of the miscellaneous submissions:

- a. There is a gap of only 6 months and 10 days and not 7 months as mischievously alleged by the exporter. The domestic industry has submitted the application five months from the date of ending of POI in terms of the Trade Notice No. 15/2018 dated 22nd November 2018. Thus, the petition was timely filed.
- b. The time limits prescribed in the manual are only internal guidelines and not statutory deadlines which the Authority may waive, and the right of waiver is mentioned in the disclaimer to the manual
- c. The recent amendment to the AD Rules made vide Notification No. 9/2020- Customs (NT) dated 2 February 2020 came after the initiation of investigation and any amendment cannot be imposed retrospectively unless it is specifically provided.

F.2 Views of the other interested parties

28. Following are the submissions made by the Applicant with regard to scope of the domestic industry and standing:

- a. There is a gap of 7 months between the date of initiation and the end of period of investigation. It is an established principle, as per manual and the recent amendment to the AD Rules made vide Notification No. 9/2020- Customs (NT) dated 2 February 2020, that the period of investigation cannot be older than 6 months on the date of initiation. It is submitted that such an outdated period of investigation will not be able to reveal the true picture of the market and will lead to skewed results.

F.3 Examination by the Authority

29. As regards submissions concerning the length of POI or its proximity to date of initiation, the Authority notes that the POI chosen for the case is consistent with the legal position at the time of initiation and the practice being followed by the Authority. While it may be desirable to minimise the time gap between end of the POI and date of initiation in order to keep date of initiation as proximate as possible to the end of the POI, the Authority notes that there was no legal provision proscribing initiation of an investigation if the POI was older than six months on the date of initiation. The application was filed by the applicant within the time limits prescribed by the Authority and therefore the Authority was required to consider the same within the framework of legal provisions prevailing at the time of initiation.

30. It is further noted that the Rules have been amended vide Notification No. 9/2020- customs (N.T.) dated 2nd February 2020 wherein Rule 2 (da) and Explanation to Rule 22 have been inserted, incorporating the following provisions:

“The POI shall:-

- (i) *not be more than six months old as on the date of initiation of investigation.*
- (ii) *be for a period of twelve months and for the reasons to be recorded in writing the designated authority may consider a minimum of six months or maximum of eighteen months.”*

31. It is, however, noted that the above amendment has been carried out after the initiation of the present investigation.

32. With regard to 15 months POI taken by the Authority in this investigation, it is noted that the application in the instant case was filed on 3rd December, 2019. The Authority considers that the investigation period should normally be 12 months period. The Authority can however consider a period longer than 12 months (15 or 18 months), if it is found that such longer period also includes a complete accounting year, and there are no peculiar facts showing that fixation of a longer period of 15 or 18 months as the investigation period would be inappropriate. Considering all aspects, the Authority considered it appropriate to have the POI of 15 months.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

33. Under Section 9A(l)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

- (i) the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
- (ii) when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either—
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
 - (b) Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

G.1 Views of the domestic industry

34. The following submissions have been made by the Applicant with respect to determination of normal value, export price and dumping margin:

- a. China PR should be considered as a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by investigating authorities in other countries.
- b. The cost and price of the Chinese producers cannot be relied upon for determination of normal value, and accordingly, the normal value should be determined in accordance with the provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
- c. The subject goods are produced mainly in China PR and India. Normal value could not be determined based on price or constructed value in a market economy third country. The Applicant has determined the normal value of subject goods based on cost of production of the subject goods in India with addition of administrative & selling expenses and a reasonable amount of profit.
- d. The dumping margins determined in the preliminary findings are understated. The responding exporters should be treated as non-cooperative and accordingly allowed the highest margin determined for the non-cooperative exporters. The impact of dumping on the domestic industry is significant.
- e. The Chinese producers have not even filed a MET questionnaire and the responding producers/exporters are not entitled to be accorded individual normal value as they have not established that normal value can be determined based on their own data.
- f. The Authority can only consider their data for export price determination, that too if the same is complete in all respect. The applicant requests the Authority to re-examine and determine the export price for each of the responding exporters.
- g. The normal Value has been constructed based on the cost of production of the domestic industry which is highly business-sensitive information, disclosure of which would be of significant competitive advantage to the competitors and consumers and would seriously impact the interest of the applicant.
- h. Chinese producers are practicing dumping all over the world and the Authority may direct them to provide full invoice-wise details of exports to the rest of the world and determine the dumping margin in third country exports.

G.2. Views of the other interested parties

35. The following submissions have been made by the Applicant with respect to determination of normal value, export price and dumping margin:
- a. The dumping margin should be determined based on the data provided by the respondent
 - b. The analysis of the treatment of each cost element in the computation of normal value should be provided for computation of dumping margin. This is against the provisions of transparency in AD law.
 - c. The Normal value calculated by the Authority is unreliable as the Authority should have first utilized the first two methods before constructing the Normal Value. Reliance placed on Hon'ble Supreme Court decision in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others, (2005) 3 SCC 39 and anti-dumping cases of European Commission against China PR.
36. None of the interested parties has made any submission with regard to MET Claim. It has been submitted that the export price, landed value and dumping margin should be determined on the basis of the actual data in the exporter's questionnaire response submitted to the Authority.

G.3 Examination by the Authority

G.3.1 Determination of normal value and export price

Market economy status for Chinese Producers

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

- (i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*
- (ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."

38. It is noted that while, the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since none of the responding producers and the exporters from China PR have submitted supplementary questionnaire response, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
39. Accordingly, the normal value and export price for the producers/ exporters from the subject country have been determined as below.

Determination of Normal Value for all producers in China PR

40. As none of the producers from China PR have filed the Supplementary Questionnaire response for market economy treatment, the normal value has been determined in accordance with Para 7 of Annexure I of the Rules, which provides as follows

“In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

41. In the absence of sufficient information on record, regarding the other methods as enshrined in Para 7 of Annexure I of the Rules, the Authority has determined the normal value by considering the method on “any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin”. The Authority has, therefore, constructed the normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses an addition of reasonable profits. Accordingly, the constructed normal value so determined for Chinese producers/ exporters is mentioned in the dumping margin table below.
42. With regard to the contention that the normal value should be determined after exhausting the first two methods before constructing the Normal Value, the Authority notes that the domestic industry contended that product under consideration is produced mainly in India and China PR. The contention has been examined and it is noted that there is no information available with regard to the normal value of the product under consideration in the market economy third country.
43. As regards the contention with respect to the disclosure of computation of normal value, the Authority notes that the normal value is constructed on the basis of cost of production in India, duly adjusted, including selling, general and administrative expenses an addition of reasonable profits, and the same cannot be revealed being a business sensitive information. The constructed normal value as determined is mentioned in the dumping margin table.

Determination of Export Price

44. M/s Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co. Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the product to India through related company i.e M/s Zhejiang Jingxin Pharmaceuticals Import and Export Co Ltd, (Exporter). Following the receipt of response, a deficiency letter was sent to cooperating producer and exporter asking them to submit replies to the deficiencies. The cooperating producer and exporter has submitted replies to deficiencies, and response has been examined. It is noted that during the POI, M/s Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd., China PR has exported *** MT of subject goods through related company i.e. M/s Zhejiang Jingxin Pharmaceuticals Import and Export Co Ltd, (Exporter). The Authority has examined the details of the exports given in the questionnaire response filed by the producers/exporters. The adjustments towards inland freight, ocean freight, handling and

customs charges, insurance, commission, port expenses, bank charges, and VAT refund has been examined through desk verification to the extent feasible, and accordingly the export price for the PUC at ex-factory level of the Producer i.e. M/s Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd has been determined, and shown in the dumping margin table.

M/s Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd, China PR

45. M/s Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/exporter has given details of the exports of subject goods to India in Appendix 3A of the exporters' questionnaire response. The responding producer/exporter has also clarified that Appendix 3B and Appendix 3C are not applicable in their case because there are no sales to related Indian customers and the responding producer/exporter has not exported the subject goods to India through a trading company. It is noted that during the POI, M/s Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd, China PR has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges and non-refundable VAT. The export price along with the adjustments have been examined through desk verification to the extent feasible and accordingly, the export price for the PUC at ex-factory level of the Producer i.e., Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd has been determined which is mentioned in the dumping margin table.

M/s Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co, China PR

46. M/s Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd. is a producer of the subject goods in China PR and has exported the subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/exporter has given details of the exports of subject goods to India in Appendix 3A of the exporters' questionnaire response. The responding producer/exporter has also clarified that Appendix 3B and Appendix 3C are not applicable in their case because there are no sales to related Indian customers and the responding producer/exporter has not exported the subject goods to India through a trading company. It is noted that during the POI, M/s Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd., China PR has exported *** MT of subject goods directly to unrelated customers in India. The responding producer/exporter has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other related expenses, credit cost, bank charges and non-refundable VAT. The export price along with the adjustments have been examined through desk verification to the extent feasible, and accordingly, the export price for the PUC at ex-factory level of the Producer i.e. Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co, has been determined which is mentioned in the dumping margin table.

Export Price for all other producers/exporters from China PR

47. The export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available, taking into account the data of the co-operating exporters from that country.

G.3.2 Dumping Margin

48. On the basis of normal value and export price, as determined above, the dumping margin for producers/exporters from China PR has been determined and the same is mentioned in the table below:

Dumping margin table

Country	Producer	Normal Value / CNV (US\$/Kg)	Export Price (US\$/Kg)	Dumping Margin (US\$/Kg)	Dumping Margin	Dumping Margin Range
China PR	Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	20-40
	Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Others	***	***	***	***	20-40

H. INJURY AND CAUSAL LINK

H.1 Views of the domestic industry

49. The submissions made by domestic industry with regard to injury and causal link are summarized as follows:

- a. The volume of imports has shown significant increase in absolute terms as well as in relation to production & consumption in India.
- b. Imports from the subject country have increased throughout the injury period.
- c. While the market share of the imports has increased, the market share of the domestic producers as a whole has declined.
- d. The imports significantly are undercutting the prices of the domestic industry in the Indian market.
- e. The dumped imports have suppressed the prices of the domestic industry.
- f. The domestic industry enhanced its capacity for the product in view of present and potential demand for the product in India and globally. However, the production and sales of the domestic industry have declined over the injury period, despite increase in demand.
- g. Due to increasing imports, additional capacity with the domestic industry has remained largely unutilized, resulting in decline in capacity utilization over the injury period.
- h. Profitability of the domestic industry with respect of product under consideration has declined consistently over the injury period and the domestic industry is suffering losses in the period of investigation.
- i. The domestic industry is suffering cash losses and negative return on capital employed in the period of investigation.
- j. Market share of domestic industry declined over the injury period despite existence of sufficient capacities in the Country.
- k. Inventories have shown significant increase throughout the injury period. Inventories in the period of investigation were 4.2 times of inventories in the base year.
- l. Productivity has declined in absolute as well as relative terms despite addition in capacities made by the domestic industry.
- m. The Applicant produces few other goods as well and therefore employment and wages are not solely dependent on the subject goods performance.
- n. The dumping margin is not only more than de-minimis but also substantial. The impact of dumping on the domestic industry is adverse.
- o. Growth of the domestic industry in terms of the majority of parameters such as, production, sales, market share, profits, return on investment, cash profits, etc. is adverse.
- p. Given the state of affairs of the domestic industry where manufacture and sale of the product is consistently not performing well because of persistent dumping over last few years, substantial fresh investments cannot even be imagined.
- q. There is no inaccuracy in the data. The interested party lacks appreciation of the data.
- r. Applicant is one of the major drug producers in India and it produces several Bulk Drugs (API) having production of about 50 products. In a large number of products, India and China PR are the only producers globally. The Chinese producers wish to eliminate production in India to acquire a global monopoly.
- s. The profits in the annual report are not reflective of the product under consideration. Having a 7-10% profit before tax cannot be considered as extremely high profit.
- t. The Authority recommends anti-dumping duty after verification of all data & taking into consideration import quantities and import prices and presently, Aarti has an anti-dumping duty only on one product - Ofloxacin. Thus, the opposing parties' claims are baseless and not in the interest of the nation.

- u. The data provided by the applicant has been verified by the Authority. The overall performance of the domestic industry has been adversely impacted due to dumped imports.
- v. Under Anti-dumping rules, 3% of dumped imports to total is considered as significant and the affected domestic industry can seek relief under antidumping law and in the present case, the imports from the subject country are significantly higher percentage of demand as compared to the percentage considered under rules. The imports from the subject country have increased by about 28% during the injury period which cannot be considered as insignificant.
- w. It is without basis that export sales price is lower than the domestic sale price. The domestic industry has claimed the injury suffered by it based on its domestic performance. Possible adverse profits in exports cannot affect profits in domestic operations. Further, the domestic industry is exporting at sub-optimal prices not out of choice or preference, but out of compulsion created by dumping practices.
- x. The exporter is trying to defy the figures which have been verified and considered by the Authority. The increase in inventory has been upheld by the Authority. As far as employment and wages are concerned, the domestic industry has not claimed injury on these accounts. It is important to provide information on all injury parameters. It is not important to show injury in all injury parameters.
- y. The demand for subject goods has not fallen and there is no basis with the interested party for making such statements about the domestic industry.
- z. The domestic industry expanded its capacity to meet the Indian demand and despite an increase in capacities, the applicant was in profits.
- aa. The price ceiling imposed under the Drugs (Price Control) Order, 2013 (“DPCO”) is for formulation and not on API or Bulk drugs.
- bb. The issue of public health emergency due to coronavirus justifies imposition of antidumping duty up to full extent of margin of dumping. The Designated Authority should not leave the country to the mercy of Chinese producers for such products. The domestic industry is supplying these essential drugs even at the time of this pandemic without any break.
- cc. The cost of the product under consideration for treating one patient is a meagre Rs. 12, considering the selling price of Rs. 2000 per kg. and consumption of 5.81 grams product by one patient over a period of seven days. Thus, the Designated Authority may kindly ascertain the impact of the proposed ADD per patient. It would not be even the lowest price of one cup of tea on a street.
- dd. Larger public interest demands existence of viable and vibrant domestic industry. The imposition of duty is to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market while seeking the balance the injured domestic industry and the consumers. Authority need to check what is in the general interest of the country.
- ee. The present case is a fit case for imposition of anti-dumping duty up to full extent of dumping margin as the Chinese producers are operating under non-market economy situation and the injury margin is not sufficient to provide level playing field to the domestic industry.
- ff. The dumping and the injury margins claimed by the applicant were quite significant whereas the dumping margin and injury margin determined by the authority in the provisional findings are far lower than the margins claimed. The NIP determined is unduly low leading to unduly low margins and needs a reconsideration.
- gg. None of the country globally follow lesser duty rule in the manner it is applied in India and the domestic industry has received duty, de-facto, based on “least duty rule”.

H.2. Views of the other interested parties

50. The submissions made by other interested parties with regard to injury and causal link are summarized as follows:
- a. The data provided is inaccurate for various economic parameters as the indices are same for the POI as well as the Annualized POI. The petition did not meet the accuracy and adequacy test established under AD Rules and has several deficiencies as per Trade Notice 15 of 2018 checklist.

- b. The Petition cannot be relied on, and no submissions can be made concerning the injury caused due to inaccurate data provided by the applicant. The Authority should ask the Petitioners to provide a revised Petition, to make the required submissions.
- c. Aarti Drugs Ltd. is a regular user of Trade remedial measures (TRM) and is not suffering any injury.
- d. As per annual report, Applicant is making extremely high profits and giving out handsome dividends. Such a high level of profitability, while also simultaneously suffering an injury in so many products indicates that Applicant intends to create an unfair market space for itself through such measures.
- e. Domestic industry is not suffering a material injury due to subject imports.
- f. Mere 28% increase in imports is not sufficient to determine a significant increase in imports, particularly in the face of such humongous production by the domestic producers.
- g. The subject imports occupy a very small market share in India.
- h. The trend for Imports in relation to Production and consumption is misleading.
- i. No price suppression or depression caused by imports from the subject country. The sales realization from domestic sales is much higher than the sales realization from export sales.
- j. The import price has also moved commensurate to the cost of production.
- k. No causal link between the low sales realization of the domestic industry and subject imports. The gap between the cost and sales realization from domestic sales is not high.
- l. The prices for the subject goods are low globally and not only in India which cannot be attributed to any price pressure exerted by imports from the subject country.
- m. There is an improvement in relevant economic parameters of the domestic industry.
- n. The fall in domestic sales is attributed to the sharp decline in demand in 2017-18, and the business decisions administered by the domestic industry.
- o. Other producers have been able to retain their position in the market despite the decline in demand in 2017-18.
- p. The claims of increased inventory by four fold seems to be inaccurate and unreliable as there has been a decrease in production and increase in the total sales being made.
- q. No injury in terms of employees since there has been an increase of employees from the base year.
- r. The fall in productivity per day can be linked to the reduction in production, owing to the fall in demand and questionable business decisions relating to enhancement of capacity made by the domestic industry.
- s. A deep plunge in profit for the domestic industry in the year 2017-18 and the POI, considering that the margin between the cost price and sales price is very slight.
- t. The difference between PBT and PBIT is that of the interest costs. The gap between the two are widening, but it is not reflected in the interest cost.
- u. Increase in capacity and fall in capital employed has also bound to affect the returns earned by the company.
- v. The Authority needs to verify the profitability claims made by the domestic industry, as the data does not appear to be accurate.
- w. Injury, if any, is attributable to sources other than subject imports such as increase in capacity in the time of decline in demand and sharp increase in costs of the product made domestic industry face a heavy losses which affected the profitability of the domestic industry in the POI.
- x. The difference in PBT and PBIT does not match the trend of the interest costs.
- y. The high-interest costs due to capacity expansion might be concealed.
- z. Injury is self-inflicted and cannot be attributed to the subject imports.
- aa. Huge losses due to high costs, and low export price of DI. The delta between the export price and the cost of production for exports is huge.

- bb. The domestic industry is not cost-efficient as reflected by the price pressure it is facing in the international market. It would be unfair for the subject imports to bear the burden of the inefficiency of the domestic industry.
- cc. The causal link between imports and performance of the domestic industry in terms of profit is broken. Price undercutting has remained constant during the injury period, but the profits have fallen by significant margins.
- dd. The Authority should not recommend anti-dumping duty and determine that there is no evidence of dumping; injury and causal link.
- ee. There is a public health emergency due to the spread of coronavirus and Ciprofloxacin HCL is one of the main chemical components of the drug used for curing various infections and pneumonia is a major component of the wide-spread and fatal coronavirus.
- ff. It would not be in the public interest to impose a duty on imports which could save the lives of people of the country. The domestic industry has hiked up high costs, and the drug could be left unavailable to the Indian masses.
- gg. Due to the epidemic, the domestic industry is unable to purchase enough raw materials from China PR resulting in a lack of domestic supply. Therefore, the imposition of anti-dumping duty will not prove to be beneficial for India's local downstream pharmaceutical companies.
- hh. The imposition of preliminary duty was not warranted as there exists no injury, and no causal link between the imports from the subject country
- ii. Reliance placed on the *investigation conducted on “Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand*, wherein the Authority had terminated the investigation as other producers in India were doing well.
- jj. The injury to the DI is fabricated and not substantiated with corroborative evidence as high profits recorded in financial statements during the entire injury analysis period and POI and the production and sale has significantly increased.
- kk. The Authority has not considered all the injury parameters pursuant to Rule 11 read with Annexure-II AD Rules and the analysis does not satisfy the requirements provided in Article 3.4 of WTO which directs the Applicant to not only establish an actual decline but also the effects of potential decline must be demonstrated.
- ll. There is no Price Underselling since the NIP will be lower than the landed value. The raw material inefficiency on the procurement of raw material is also accepted in Annual Report.
- mm. The NIP computed by the authority disregard the inability of the DI to a) procure raw materials at an internationally competitive price, and b) Manufacture the goods using the optimum resources (best production utilization ratio) across all producers of the subject goods in India. This calculation of NIP is inconsistent with the decision of the Hon'ble Supreme Court of India in Reliance Industries Limited vs Designated Authority and Ors.
- nn. The cost of production of subject goods may be recalculated based on the cost of manufacturing at least 3 producers in India including Neuland Laboratories Ltd and Dr Reddys Laboratories' as these companies are not incompetent.
- oo. The supporter Industry is running into exceptionally high profits during the entire injury analysis period and the period of investigation.
- pp. Injury being self-inflicted and the increase in sales value, constant raw materials cost and increased profitability of the supporter industry indicate that the domestic industry has internal inefficiencies.

H.3. Examination of the Authority

51. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, "... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...". In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the

like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules.

52. The Authority has taken note of various submissions made by the Domestic Industry and other interested parties on injury and causal link and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis undertaken ipso facto addresses submissions made by the domestic industry and other interested parties.

H.3.1 Volume effect of the dumped imports

a. Assessment of demand/apparent consumption

53. For the purpose of the present investigation, the Authority has taken into consideration the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources.

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI (A)
Domestic Industry Sales	MT	908	810	648	1007	806
Supporters Sales	MT	***	***	***	***	***
Sales of Other Producers	MT	***	***	***	***	***
Total imports from the subject country	MT	117	171	217	347	278
Imports from other countries	MT	-	-	-	8	6
Total Demand/Consumption	MT	2,730	2,837	2,475	3,444	2,755

54. It is seen that while the demand for the product under consideration declined in 2017-18, it has increased during the period of investigation. As compared to the base year, the demand for the subject goods has marginally increased.

b. Import volumes from subject country

55. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports from subject country, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction-wise import data procured from DGCI&S. The volume of imports of the subject goods from the subject country has been analysed as under:

Import Volume	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI(A)
Subject Country-China PR	MT	117	171	217	347	278
Other Countries	MT	-	-	-	8	6
Total Imports	MT	117	171	217	355	284
Total Demand/Consumption	MT	2,730	2,837	2,475	3,444	2,755
Production	MT	3,236	3,530	3,001	3,835	3,068
Imports of subject goods from subject country in relation to						
Total Indian Production	%	3.62%	4.85%	7.23%	9.06%	9.06%
Demand/Consumption	%	4.29%	6.04%	8.77%	10.09%	10.09%

56. It is noted that:

- The volume of dumped imports has increased significantly in absolute terms over the injury period.
- The imports have shown a significant increase in relation to domestic production and consumption.

H.3.2 Price effect of the dumped imports

57. In terms of Annexure II (ii) of the Rules, with regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.

a. Price undercutting

58. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry, all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex-works level has been considered for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Price Undercutting

Particulars	Units	China PR			
		2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Landed price of imports	Rs/Kg	1743	1295	1447	1819
Net Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs/Kg	***	***	***	***
	%	***	***	***	***
	Range	(0-10)	0-10	0-10	0-10

59. It is seen that the landed prices of the subject goods were below the selling price of the domestic industry. Further, marginal price undercutting is indicative of stiff competition between the foreign producers and domestic industry.

b. Price suppression and depression

60. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared as below:

Price Suppression and Depression

	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI-A
Cost of Sales	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	97	127
Selling Price	Rs/Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	93	115
Landed Price-China PR	Rs/Kg	***	***	***	***
Indexed	Indexed	100	74	83	104

61. It is seen that while the landed price of imports from subject country were above the cost of sales of domestic industry in the year 2015-16 and 2016-17, it declined thereafter to a level lower than the cost of sales. During the period of investigation, the landed price of imports is significantly below the cost of sales. As a result, even though the selling price of the domestic industry has increased in the period of investigation, as compared to the base year, the increase is much less than the increase in cost of sales during the same period. Thus, the imports have prevented price increases, which otherwise would have occurred. The domestic industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country.

c. Price underselling

62. The Authority has also examined price underselling suffered by the domestic industry on account of dumped imports from the subject country. For this purpose, the non-injurious price for the domestic industry has been compared with the landed price of imports as obtained from the DGCI&S import data.

Price Underselling		
Particulars	Unit	Price Underselling
Landed Price	Rs/Kg	***
Non-Injurious Price	Rs/Kg	***
Price Underselling	Rs/Kg	***
Price Underselling	%	***
Price Underselling	Range	0-20

63. It is noted that the landed value of subject imports was below the non-injurious price of the domestic industry, thus resulting in significant price underselling.

H.3.3 Economic parameters of the domestic industry

64. Annexure II to the Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. The various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below.

a. Production, capacity, sales and capacity utilization

65. Capacity, production, sales and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is as follows:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	107	140	112
Total Production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	92	115	92
Capacity Utilization	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	85	82	82
Domestic Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	89	71	111	89
Export Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	118	102	134	107
Total Sales	MT	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	83	119	96

66. It is seen that:

- a. The domestic industry has increased its capacity during the injury period.
- b. While capacity with the domestic industry increased, its production has declined post 2016-17. As a result, the capacity utilization of the domestic industry has declined.
- c. The sales of the domestic industry have declined from the base year till the year 2017-18. Though there has been increase in the period of investigation, the same remained materially lower than the volumes registered in 2015-16, even though the demand/consumption was slightly higher.

b. Market Share in Demand

67. Market share of the domestic industry and of imports was as shown in table below:

Particulars	UoM	2015-16	2016-17	2017-18	POI (A)
Domestic Industry Sales	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88	79	88
Supporters Sales	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	107	100
Sales of Other Producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	104	98
Total imports from the subject country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	150	225	250
Imports from other countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	-	-	-	100
Total Demand/Consumption	%	100%	100%	100%	100%

68. It is noted that while the market share of subject imports has increased, the share of domestic industry has declined over the period. Further, the market share of Indian industry as a whole has also declined. The decline in market share is despite increase in capacity.

c. Inventories

69. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI
Opening Stock	MT	***	***	***	***
Closing Stock	MT	***	***	***	***
Average Inventories	MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	345	418

70. It is seen that the inventories with the domestic industry have increased significantly over the injury period.

d. Profitability, return on investment and cash profits

71. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2015-16	2016-17	2017-18	POI	
					Actual	Annualized
Selling price	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	93	115	115
Cost	Rs/Kg	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	84	97	127	127
Profit/ loss	Rs/Kg	***	***	***	***	***

Trend	Indexed	100	86	(35)	(246)	(246)
Profit/ loss	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	77	(25)	(273)	(219)
Profit/ loss before Interest and Tax	Rs Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	67	16	(72)	(57)
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	78	10	(128)	(103)
Average Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	79	70	87	87
ROCE	%	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85	23	(66)	(66)

72. It is seen that

- a. The profitability of the domestic industry with respect to the product under consideration declined continuously over the injury period and the domestic industry has incurred losses during the period of investigation.
- b. Similarly, the cash and return on investment have declined, and become negative during the period of investigation.

e. Employment, productivity and wages

73. Performance of the domestic industry with regard to employment, productivity and wages over the injury period was as follows.

Employment, Productivity and Wages						
Particulars	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI	POI
Employee	Nos.	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	101	102	102
Productivity per Day	MT/Day	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	92	92	92
Productivity per Employee	MT/Nos	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	91	90	90
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103	108	159	127

74. It is seen that the number of employees remained almost at the same level during the injury period, while wages have increased. Productivity has declined with decrease in production.

f. Growth

Growth	Unit	2015-16	2016-17	2017-18	POI-A
Production (MT)	%		2.42	(10.47)	0.18
Domestic Sales Volume (MT)	%		(10.75)	(19.99)	24.28
Capacity Utilization	%		2.15	(15.17)	(2.89)

Cost of Sales (Rs/Kg)	%	(16.22)	15.69	30.82
Selling Price (Rs/Kg)	%	(16.15)	10.56	23.89
Profit/ Loss (Rs/Kg)	%	(14.04)	(141)	(606)
Cash Profit	%	(21.58)	(87.75)	(1,167.69)
ROI	%	(1.88)	(7.56)	(10.89)

75. Growth of the domestic industry with regard to production, domestic sales and capacity utilisation were negative during 2017-18, though these improved to some extent in the period of investigation. However, profits, return on capital employed and cash profits showed negative growth throughout the injury period, especially during the period of investigation.

g. Ability to raise capital investments

76. The Authority notes that domestic industry is suffering low capacity utilization and losses. Further, the return on capital employed of the domestic industry has become negative. This suggests that the imports may impact the ability of the domestic industry to raise capital investments.

h. Magnitude of dumping

77. It is noted that the subject goods are being dumped into India, and the dumping margin determined is above de-minimis and significant.

i. Factors affecting domestic prices

78. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market shows that the landed value of imported material from subject country is the benchmark for the selling price of the domestic industry. In fact, the domestic industry is matching the price of imports, and has not increased its prices in proportion to the increase in costs. This shows that the landed prices of subject goods from subject countries are affecting the prices of the domestic industry.

79. As regards contentions with regard to accuracy of the data, the present findings are being recorded on the basis of data verified through desk verification. The fact that indexed figures for POI and annualised for the POI are the same does not imply that the figures adopted are inaccurate. Since previous years are of twelve months duration whereas the POI is of fifteen months duration, the index is required to appropriately reflect the same.

80. The Authority examined the reasons for increase in cost of production. It is observed that the primary reason for increase in cost of production is the increase in one of the major raw materials involved in production of the product under consideration.

81. As regards arguments of public interest, it is noted that the purpose of anti-dumping duty is only to address unfair practice of dumping. It is also noted that none of the interested parties barring the Domestic Industry have quantified impact of proposed ADD on the eventual end usage. Further none of the interested parties have brought any evidence in support of their argument that imposition of proposed ADD will have significant adverse impact on people of the country.

82. As regards profits of the Applicant reported in the annual report, it is noted that the Applicant is a multi-product company having a large number of products. Profits reported in annual report are not reflective of the performance of the domestic industry for the product under consideration.

83. As regards the contention that the domestic industry has suffered losses in exports, it is noted that the information with regard to profits, cash profit, and return on investment is based only on domestic operations and is, therefore, not impacted due to possible losses in exports.

84. As regards the contention that the domestic industry expanded capacity despite losses in the past, the Authority notes that the information on record shows that the Applicant domestic industry was in profit earlier before expansion of capacity, and even after expansion of capacity in 2017-18, the domestic industry was in profits.

85. As regards to the contention that NIP determined is unduly low leading to unduly low margins, and none of the country globally follow lesser duty rule in the manner it is applied in India and therefore, the

Authority should recommend ADD upto full extent of dumping margin, the Authority notes that the rules require the Authority to recommend ADD considering dumping margin and injury margin. If the injury margin determined is lower than dumping margin, the Authority is required to consider such injury margin while recommending duty.

86. As regards the claim that the injury to domestic industry is fabricated and high profits are recorded in the financial statements, the Authority notes that the financial statements of the company are not reflective of the performance of product alone, and pertains to performance of the company for all its operations, in both domestic and export markets. Injury analysis is required to be done only for product under consideration and only in respect of domestic market operations.
87. As regards to the contention that all the injury parameters to be considered pursuant to Rule 11 read with Annexure-II AD Rules, it is clarified that the Authority has examined all parameters. Further, the Authority notes that it is not necessary that all parameters relating to the domestic industry show injury.
88. As regards the claim that applicant is the regular user of trade remedial measures, the Authority considers that antidumping duties have been recommended only after conducting investigations and finding that it was necessary to impose ADD to address injurious dumping.
89. As regards the submission that the injury to the domestic industry is self-inflicted and there is absence of causal link, the Authority has examined the claims of the domestic industry and interested parties. As regards contention that the domestic industry has increased capacity when demand has declined, the Authority notes that the demand of the subject goods has increased over the injury period. Further the Authority has examined the data provided by the domestic industry. The capacity of domestic industry has been enhanced in the light of increase in demand.
90. As regards to the contention that the cost of production may be calculated based on the cost of manufacturing of at least 3 producers in India including Neuland Laboratories Ltd and Dr Reddys Laboratries, the Authority notes that the information is required to be considered in respect of domestic industry. Further, since information relating to other domestic producers is not on record, the same cannot be considered for the purpose of present determination.
91. Regarding inconsistency in calculation of NIP, it is noted that the NIP has been calculated on the basis of principles laid down under the Rules. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry, duly certified by the practising cost accountant and examined by the Authority.
92. As regards the contention that supporter Industry is earning exceptionally high profits, the Authority notes that the performance of the company reported in the financial report is reflective of the performance of the company for all its operations, and not for the product alone.

I. INJURY MARGIN

93. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practising cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed as per consistent practice of the Authority.
94. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on facts available.
95. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is mentioned in the table below:

Country	Producer	Non-Injurious Price (US\$/Kg)	Landed Value (US\$/Kg)	Injury Margin (US\$/Kg)	Injury Margin (%)	Injury Margin % (Range)
China PR	Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.	***	***	***	***	0-20
	Others	***	***	***	***	0-20

I. 1 Examination of injury

96. The examination of the imports of the subject product and performance of domestic industry shows that the volume of imports has increased in absolute terms as well as in relation to production and demand in India. The imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the price underselling is also positive. The imports of subject goods from subject country has prevented price increases which otherwise would have occurred due to increase in cost of production. The domestic industry has suffered price suppression on account of import of subject goods from subject country.
97. While the capacity of the domestic industry has increased over the period, the production and sales of the domestic industry has declined when compared to the base year. The market share of subject imports has increased, while the share of domestic industry has declined over the same period. The domestic industry has suffered a decline in its profits over the injury period, and is suffering losses. The cash profits and return on capital employed of the domestic industry has declined significantly and became negative during the POI. It is also noted that the dumping margin is positive and significant.

I.2 Non-attribution analysis

98. Having examined the existence of injury, volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, the Authority has examined whether injury to the domestic industry can be attributed to any factor, other than the dumped imports, as listed under the Rules.

a. Imports from other sources

99. Since China PR accounts for 97.76% of the total imports, and imports from other countries are negligible, the imports from other countries could not have caused injury to the domestic industry.

b. Contraction in demand

100. Although the demand for the product under consideration declined in 2017-18, it has rebounded in the period of investigation. Further, the domestic industry has lost market share to the subject imports, in the present demand. Thus, the injury to the domestic industry is not on account of any contraction in demand. In any case, there is no contraction of demand during the injury period.

c. Changes in the pattern of consumption

101. There is no evidence of any change in the pattern of consumption with regard to the product under consideration. Therefore, changes in the pattern of consumption cannot be considered to have caused injury to the Domestic Industry.

d. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

102. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. No evidence has been submitted by any interested party to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

e. Developments in technology

103. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

104. The injury information examined hereinabove relates only to the performance of the domestic industry in terms of its domestic market. Thus, the injury suffered cannot be attributed to the export performance of the domestic industry.

g. Performance of other products being produced and sold by the domestic industry

105. The Authority has only considered data relating only to the performance of the subject goods. Therefore, performance of other products produced and sold are not a possible cause of the injury to the domestic industry.

I.3 Examination on causal link

106. It is thus noted that other known factors listed under the Rules do not show that the domestic industry could have suffered injury due to these other factors. The Authority has also examined whether the dumping of the product has caused injury to the domestic industry. The following parameters show that material injury to the domestic industry has been caused by dumped imports.

- a. Imports of the subject goods have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption.
- b. The market share of subject imports has increased, while the share of domestic industry has declined over the same period.
- c. The price undercutting is positive. The imports of subject goods from subject country has had a suppressing effect on the prices of the product in the market.
- d. As a result, the production and sales of the domestic industry have declined over the period.
- e. The domestic industry has suffered financial losses, cash losses and negative return on investment.

107. The essential facts of the investigation gathered by the Authority during the course of the investigation and analyzed by the Authority in the present final findings are being disclosed to the interested parties in order to enable them to offer their comments on these facts.

J. POST DISCLOSURE COMMENTS

108. Post-disclosure submissions have been received from the interested parties. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the interested parties including reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of these final findings. The issues raised for the first time in the post disclosure comments/submissions by the interested parties and considered relevant by the Authority are examined below.

J.1. Views of the domestic industry

109. The following post-disclosure submissions have been made by the domestic industry:

- a. There is no merit in the argument that the supporter industry is earning exceptionally high profits. The performance reported in the financial report is reflective of the performance of the company for all its operations, and not just for product. Further, the company is unable to fully utilize our capacities. Infact the balance sheet would make it amply clear that our company is barely making between 1.25% to 2% profit as compared to an industry average of about 7%.
- b. No demand-supply gap, Indian Industry is totally AtmaNirbhar Industry. The most compelling reason for need of imposition of duty is that India has become self-reliant. In absence of imports domestic industry and the other domestic producers are capable of catering to the total demand of the country.
- c. Estimated per annum combined capacity in India for the product under consideration is much higher than the demand/consumption in India.
- d. Imposition of anti-dumping duty would not be against public interest. It is a redressal of unfair price discrimination by the producers in other countries, which is injurious to the industry in India. It is not a protection, but rather a means of price correction. It would not restrict imports and would not affect the availability of the product to the consumers. The consumers could still maintain two or even more sources of supply.

- e. Currently there is antidumping duty only on Ofloxacin which is one out of around 50 Bulk Drugs that is manufactured by the domestic industry and contributing to the “Make in India” and Atmanirbhar Bharat” missions.
- f. The Govt has launched a “Production Linked Incentive scheme” with an objective to reduce dependency on imports for certain Essential Bulk Drugs. Ciprofloxacin HCL is featuring in that list.
- g. Due to lack of market in the presence of dumped imports, the producers are not able to perform in this product. Given the opportunity and the available market the domestic producers, not only has the capacity much more than the existing demand in the Country and cater the same, but also will be able to cater to any foreseeable increase in demand, as well as earn valuable foreign exchange for the country by undertaking exports from the surplus production, thereby truly fulfilling the vision of Aatmanirbhar Bharat insofar as the product is concerned.
- h. The Authority should not leave the country to the mercy of Chinese producers for such products. The Authority is entitled to consider whether it is a fit case where the Govt. can ignore injury margin and impose ADD upto full extent of dumping margin. Given that the product is a pharma API, and concerns Country’s health sector, with de-facto no adverse impact of proposed duty on the consumers, existence of viable and vibrant industry should be a bigger concern for the Country.
- i. The product is mainly produced in China and India, and thus the domestic production is more important in the present product. Considering the relevance & importance of the product for India’s healthcare, the Country needs domestic manufacturing unless Govt. of India is willing to leave the country at the hands of China for such essential drugs. Absence of domestic production in the product shall imply total dependency on China.
- j. The Authority earlier recommended anti-dumping duty on Penicillin-G but the Government however rejected recommendations. The prices of the product plunged in last one decade following cheaper imports from China with business becoming unviable and Indian manufacturers like Max-GB, HAL, JK Pharma and TGBL closed down the production. Alembic too had closed the Pen-G facility, but it restarted later. Contrary to the fate of Penicillin-G, in case of Metronidazole and Diclofenac Sodium, support granted by the Government led to a viable and vibrant Domestic Industry in the Country now. Country is no more dependent on imports and If required the domestic producers are having sufficient capacity to cater Indian demand. The Authority need to consider the importance of the drugs in the present time of pandemic and make nation self-sustainable.
- k. Absence of opposition from consumers shows consumers are not adversely impacted.
- l. The trade remedial measures are applied to eliminate unfair practices such as dumping due to which the domestic industry is injured. The imposition of duty is to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market while seeking the balance between injured domestic industry and the consumers.

J.2. Views of the other interested parties

110. The following post-disclosure submissions have been made by the other interested parties:
- a. The exporters have duly complied with Annexure II of the Trade Notice No. 10/2018 dated 7 September 2018 in all the responses and submissions made by them.
 - b. The law does not grant any discretion to the Authority in recommending a duty based on the full margin of dumping. Therefore, it is not legal for the Authority to recommend a duty based on the higher margin in the subject investigation.
 - c. The law for calculating the non-injurious price is also envisaged in Annexure III to the Anti-Dumping Rules and cannot be curtailed. The anti-dumping regime of India has existed since 1995 and has sufficiently protected various domestic industries of various products, including Aarti Drugs Ltd. in several investigations.
 - d. In 2015, Sun Pharmaceuticals Industries Limited who is a domestic producer of the PUC filed a petition against Notification S.O. No. 1882(E) dated 13.07.2015 issued by the National Pharmaceutical Pricing Authority fixing the ceiling price of Ciprofloxacin 250 mg. The issue raised by the company was concerning the correct methodology to calculate the ceiling price the scheduled formulation. A similar issue also arose in 2018, when Sun Pharmaceuticals Industries Limited again filed two petitions against Notification S.O. No. 2401(E) dated 28.07.2017 issued by the National

Pharmaceutical Pricing Authority fixing the ceiling price of Ciprofloxacin 250 mg and Ciprofloxacin 500 mg tablets.

- e. The unwarranted imposition of preliminary Anti-dumping duty. The Authority has, without evaluating all parameters in the petition, hastily recommend interim duties and issued preliminary finding vide Notification No. 6/36/2019- DGTR dated 15th June 2020.
- f. The Authority has incorrectly evaluated that the Domestic Industry constitutes “major proportion of the total domestic production of that article” pursuant to Article 4.1 of Agreement on Antidumping and Rule 2(b) of the AD Rules. The Respondents relied on the decision of the Appellate body in EC-Fasteners (China).
- g. The Domestic Industry has been in the consistent practice of requesting for the imposition of Anti-dumping duties on various range of its products since early '20s, and still continues to suffer injury. The other producers of the subject goods which have not participated in the investigation, have not been suffering any injury and doing better. In this regard, reliance is placed on DGTR investigation of Polyester Staple Fibre from China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand and investigation of Ball Bearings (up to 50 mm bore dia) from China PR, Poland, Russia, and Romania.
- h. The determination of normal value by the Authority is against the Hon'ble Supreme Court decision in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd. and others, (2005) 3 SCC 39. Geographically, global Ciprofloxacin production is segmented into seven key regions viz. North America, Latin America, Europe, East Asia, South Asia, Oceania, and Middle East & Africa. North America dominates the overall Global Ciprofloxacin Market. Some of the major key players competing in the global Ciprofloxacin Market are Novartis International AG, Allergan plc, Merck & Co Inc, Cipla Limited, Bayer AG, Cadila Healthcare, Glenmark Pharmaceuticals, Hexal, Sanofi Synthelabo, Pfizer, and Mylan Laboratories Ltd among others. Therefore, the conclusion that Ciprofloxacin is produced mainly in India and China PR has no substance and construction of normal value on the basis of cost of production in India does not have any merit.
- i. The cost of production of Domestic Industry is too high due to unavailability of raw material from China PR.
- j. The DI is continuously hiring employees and wages have increased from injury analysis period to the Period of investigation.
- k. Production of the DI has increased by 54% when compared to the year 2015-2016 and has recorded a steady Y-o-Y growth of more than 10% each year since 2015-2016.
- l. The Domestic Industry is self-claiming that it has achieved the highest revenue and Profit Before Tax (PBT). The growth in profitability of the Domestic Industry is 27.51% when compared to the year 2017-2018 on a standalone basis.
- m. Godavari Drugs Ltd., Domestic Producer of Ciprofloxacin, mentioned that 91% to the total turnover of the company comes from Ciprofloxacin itself (Page No. 17 of annual financial statement of year 2018-19), and the company is running into profits of more than 50% during the POI i.e., they are doing exceptionally well.
- n. The Godavari Drugs Ltd. has not been incurring any loss rather having positive PAT/EPS as given above during the previous financial years.

J.3. Examination by the Authority

- 111. The Authority notes that most of the submissions by the domestic industry and other interested parties are repetitive in nature. These submissions have already been examined at appropriate places in this finding. Further, the Authority has examined additional/new relevant submissions of the interested parties as under
 - a. As regards confidentiality claims of interested parties, as stated above, the Authority has considered the confidentiality claims of various interested parties including the foreign producers, and on being satisfied, allowed the same.
 - b. As regards the contention regarding the filing of petitions against Notification S.O. No. 2401(E) dated 28.07.2017 issued by the National Pharmaceutical Pricing Authority fixing the ceiling price of Ciprofloxacin 250 mg and Ciprofloxacin 500 mg tablets, the Authority notes that the price ceiling

imposed under the Drugs (Price Control) Order, 2013 (“DPCO”) is for formulation and not on API or Bulk drugs whereas the present investigation is for APIs falling under chapter 29 whereas ciprofloxacin formulation falls under chapter 30 of the Customs Tariff Act.

- c. A number of interested parties have disputed existence of injury to domestic industry. The interested parties have pointed out at improvement in performance of the Domestic Industry in respect of few injury parameters. It is noted that the performance of the Domestic Industry has improved in respect of some parameters. However, it is well established legal position that it is not necessary that performance of domestic industry should show deterioration in respect of each injury parameter, and improvement in some parameters does not imply absence of injury. It is therefore held that so long as the performance of Domestic Industry shows deterioration in respect of some parameters and such deterioration outweighs positive developments in other parameters, it can be concluded that the Domestic Industry has suffered injury.
- d. As regards the contention that the other producers of the subject goods which have not participated in the investigation, have not been suffering any injury and doing better, the Authority notes that information relating to other domestic producers is not on record, and the interested parties have not provided any evidence to support their contention. The Authority considers that it would not be appropriate to conclude anything regarding the existence or otherwise of injury suffered by other producers for the purpose of present determination.
- e. As regards the contention regarding production of Ciprofloxacin globally and construction of normal value, it is noted that the product under consideration is Ciprofloxacin HCL APIs falling under chapter 29, which is mainly being produced in India and China. The interested parties have referred to ciprofloxacin formulation falling under chapter 30 of the Customs Tariff Act, which is beyond the scope of product under consideration in the present investigation.
- f. As regards the contention regarding alleged high cost of production of Domestic Industry due to unavailability of raw material from China PR, the Authority has considered actual cost incurred by the domestic industry and reported in the records. The cost of production reported by the domestic industry have been verified by the Authority.
- g. As regards alleged profits earned by the supporter company, the Authority notes that the present finding is on the basis of information of domestic industry.
- h. As regards reference to the past investigations concerning Polyester Staple Fibre Ball Bearings, the Authority notes that even determination is based on facts of that particular case. It would not be appropriate to refer to any past determination without establishing its comparability to the present case.
- i. As regards decision of Hon'ble Supreme Court decision in Shenyang Matsushita S. Battery Co. Ltd. v. Exide Industries Ltd., the Authority notes that none of the interested parties have provided any evidence with regard to cost or price of the product under consideration in a market economy third country, or price from such market economy third country to other countries including India.
- j. As regards alleged increase in wages and employees, it is noted that there is no abnormal increase in costs on these accounts.

K. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

- 112. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Interested parties have not established that imposition of duties is going to adversely impact the public interest.
- 113. It is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.

O. CONCLUSION

114. After examining the submissions made by the interested parties and issues raised therein, and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- The product under consideration has been exported to India from the subject country below its normal value.
 - The Domestic Industry has suffered material injury.
 - Material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject country.

P. RECOMMENDATIONS

115. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the Domestic Industry, exporters, importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the authority is of the view that imposition of Anti-Dumping is required to offset dumping and injury. Therefore, Authority recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country.
116. In terms of provision contained in Rule 4(d) & Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends impositions of anti-dumping duty equal to lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority, therefore, considers it necessary and recommends imposition of anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject countries in the form and manner described hereunder from the date of issue of the notification of imposition of provisional duty by the Central Government vide Notification No. 28/2020-CUSTOMS (ADD) dated 2nd September, 2020. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of imposition of provisional duties, on all imports of goods described at Column 3 of the duty table, originating in or exported from China PR.

DUTY TABLE

Serial number	Tariff Heading*	Description of Goods	Country of Origin/ or export	Country of Export	Producer	Duty Amount	Currency	Unit
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	29419030	Ciprofloxacin Hydrochloride	China PR	Any country including China PR	Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.	2.38	US\$	Kg
2	29419030	Ciprofloxacin Hydrochloride	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.	0.91	US\$	Kg
3	29419030	Ciprofloxacin Hydrochloride	China PR	Any country including China PR	Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd.	1.87	US\$	Kg
4	29419030	Ciprofloxacin Hydrochloride	China PR	Any country including China PR	Any producer other than serial number 1, 2, and 3	3.27	US\$	Kg
5	29419030	Ciprofloxacin Hydrochloride	Any country other than China PR	China PR	Any	3.27	US\$	Kg

*Custom classification is only indicative.

117. Subject to the above, the Preliminary Findings notified on 15th June, 2020 is hereby confirmed.

FURTHER PROCEDURE

118. An appeal against these findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Exercise and Service tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act, 1975.

B. B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority